● वर्ष-3
● अंक-131
रायपुर, बुधवार
10 जनवरी 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› ठंड के मौसम में कपड़ों से ...

इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की डगर कितनी कठिन?

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पक्ष और विपक्ष में सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है. भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए 28 दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का गठन किया है. कई दौर की बातचीत और बैठकों के बाद लगभग तमाम विपक्षी दल एक मंच पर तो आ गए हैं लेकिन कई राज्यों में उनके लिए सीट बंटवारा बेहद कठिन होने जा रहा है. मजबूत गठबंधन के निर्माण के बाद सभी घटक दल गठबंधन के तहत अधिक से अधिक सीट हासिल करना चाहते हैं. गौरतलब है कि कई ऐसे दल एक मंच पर साथ आए हैं जिनके बीच पहले कभी गठबंधन नहीं हुए थे. साथ ही इंडिया जैसे कुछ ऐसे भी दल हैं जिन्होंने कभी भी गठबंधन के तहत चुनाव ही नहीं लड़ा है.

महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं. अगर पिछले 5 चुनावों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिली है. 1999 के चुनाव में कांग्रेस को जहां 10 सीटों पर जीत मिली वहीं 2004 में 13 ,2009 में 17 सीटों पर जीत मिली लेकिन 2014 और 2019 में कांग्रेस को महज 2 और 1 सीटों से संतोष करना पड़ा. वही हालात एनसीपी के भी देखने को मिले हैं. एनसीपी के सीटों में भी साल 2009 के चुनाव के बाद से भारी गिरावट हुई है. शिवसेना को 2009 के बाद से अच्छी सफलता मिली है. लेकिन इन दोनों ही चुनावों में शिवसेना बीजेपी गठबंधन का हिस्सा रहा था. तीनों ही दलों ने मिलकर अब तक किसी भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है. हालांकि एनसीपी और शिवसेना में टूट के कारण राजनीतिक हालात में काफी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं.

बिहार में सीट बंटवारे का कैसे होगा समाधान?- बिहार में अगर पिछले 5 लोकसभा चुनाव के रिकॉर्ड को देखा जाए तो जदयू के आंकड़ों में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं. 1999, 2009 और 2019 में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था वहीं 2004 और 2014 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था. राजद का प्रदर्शन 2004 के अलावा सभी चुनावों में अच्छा नहीं रहा है. वही हालात कांग्रेस के भी रहे हैं. हालांकि विधानसभा चुनावों के आंकड़ों और वोट शेयर को अगर देखा जाए तो राजद सबसे बड़ी दल के तौर पर देखी जा सकती है. हालांकि राजद, जदयू और कांग्रेस के एक मंच पर आने के कारण काफी बदलाव हो सकते हैं.

पंजाब में कांग्रेस का रहा है दबदबा, लेकिन क्या आप मानेगी? -पंजाब में राजनीतिक हालात पिछले 2 चुनावों में काफी बदल गए हैं. 1999 से लेकर 2009 तक जहां कांग्रेस का मु य मुकाबला अकाली दल के साथ होता रहा था और कांग्रेस को अच्छी सफलता भी मिलती थी लेकिन 2014 के चुनाव में पहली बार हिस्सा लेते हुए आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली. हालांकि 2019 के चुनाव में आप को महज एक सीट मिली और कांग्रेस ने फिर वापसी करते हुए 8 सीटों पर कब्जा कर लिया. राज्य में लोकसभा की 13 सीटें हैं. हालांकि आंकड़ों के आधार पर माना जा रहा है कि 6 सीटों पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही है.

पंजाब की राजनीतिक आंकड़ों के आधार पर मंयक मिश्रा का कहना है कि हालांकि पंजाब में अभी आप की सरकार है इस वजह से संभव है कि कांग्रेस और आप में 7 और 6 सीटों पर सहमति बन जाए.

दिल्ली का क्या है समीकरण?- 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था. पार्टी को 6 और 7 सीटों पर जीत मिली थी. हालांकि 1999, 2014 और 2019 के चुनावों में कांग्रेस को एक भी सीटों पर जीत नहीं मिली थी. 2014 में आम आदमी पार्टी के एंट्री के बाद आप को भी दिल्ली में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली. हालांकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में यहां 4 और 3 के आधार पर सीटों का बंटवारा हो सकता है. हालांकि विधानसभा के पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस के मतों में भारी गिरावट देखने को मिली है.

बंगाल में ममता और कांग्रेस में बनेगी बात?- बंगाल में पिछले 5 चुनावों में से अतिम तीन में टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया है. 2004 में हार के बाद से टीएमसी ने 2009 और 2014 में जहां 19 और 34 सीटों पर जीत दर्ज की वहीं 2019 में भी उसे 22 सीटें मिले. टीएमसी का गठन कांग्रेस से अलग होकर ही हुआ था. कांग्रेस के आंकड़े हर चुनाव में अधिकतम 6 और कम से कम 2 पर रहे हैं. बंगाल में कांग्रेस पिछले कुछ समय से वामदलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है. इस बार कांग्रेस की मांग 5 सीटों की है लेकिन डेटा के आधार पर कांग्रेस को अधिकतम 4 सीटों के मिलने का अनुमान लगाया जा सकता है. वोट परसेंट और विधानसभा के आंकड़ों के आधार पर यह माना जा सकता है कि बंगाल में टीएमसी कांग्रेस की तुलना में बेहद मजबूत है.

25 साल के आंकड़ों से समझिए

न्याय योजना की चौथी किस्त देगी भाजपा सरकार: साव

लोरमी। बिलासपुर के मुंगेली जिले के लोरमी नगर के जरहागाँव में आयोजित रा'य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में मु य अतिथि की भूमिका में आए प्रदेश के उपमु यमंत्री अरुण साव ने किसान के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितैषी है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा पिछले सरकार के राजीव गांधी न्याय योजना धान खरीदी की चौथी किस्त की राशि जिसे कांग्रेस सरकार किसानों को नहीं दी थी। उस पैसे को भी हमारी सरकार देगी। बात अगर किसानों के हितों की है तो सरकार बदल जाने से किसानों के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों की चिंता करने वाली सरकार है। हम किसानों के अधिकार की वो सारी चीजें देने के लिए तैयार हैं जो मोदी की गारंटी के तहत घोषणा किया गया था। साथ ही पिछले सरकार के फैसले किसानों को दिए जाने वाले राजीव गांधी न्याय योजना की राशि भी किसानों को दिया जाएगा।

बिलासपुर के मुंगेली जिले के लोरमी नगर के जरहागाँव में आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में मु य अतिथि की भूमिका में आए प्रदेश के उपमु यमंत्री अरुण साव ने किसान के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितैषी है।

साय सरकार की कैबिनेट की बैठक आज- बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक का एजेंडा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है।

इसमें राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भी मंथन हो सकता है।

उतरते ही लगाया गले, रेड कारपेट पर हाथ पकड़कर चलते आए नजर, मोदी और यूएई के राष्ट्रपति की दोस्ती

नई दिल्ली। पीएम मोदी यूएई की यात्रा पर गए थे तो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन अल नाहयान ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अबू धाबी एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी की थी। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को अहमदाबाद में उतरते ही गले लगाया और फिर रेड कारपेट पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मंगलवार को अहमदाबाद हवाई अड्डे से गांधीनगर तक एक भव्य रोड शो का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री द्वारा हवाई अड्डे पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का स्वागत करने के बाद शाम को 3 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो शुरू हुआ। विदेश मंत्रालय ने हवाई अड्डे पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें साझा कीं और कैप्शन दिया दोस्ती के मजबूत बंधन की पुष्टि। एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक का गर्मजोशी से स्वागत किया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की अयोग्यता पर नतीजे इंतजार! नार्वेकर और शिंदे की मुलाकात

मुंबइ, (ए)। मुंबई। शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले का अंतिम परिणाम 10 जनवरी को घोषित किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में मु यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की। लेकिन इस दौरे पर उद्धव ठाकरे ने आपत्ति जताई है। इसके खिलाफ ठाकरे गरुप ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। क्या इनके बीच कोई मिलीभगत है? ऐसा सवाल उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा ठाकरे समूह के सचेतक सुनील प्रभु ने दाखिल किया है। इसमें उन्होंने कहा कि मु यमंत्री शिंदे, जिन पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है, उन्होंने नतीजों से तीन दिन पहले नतीजे देने वाले राष्ट्रपति नार्वेकर से मुलाकात की। ये बहुत गलत है। ठाकरे ने अर्जी में कहा है कि वह इसके जरिए नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा देकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिका पर फैसले से पहले महाराष्ट्र के मु यमंत्री एकनाथ शिंदे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के बीच बैठक पर आपत्ति जतायी। ठाकरे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह हलफनामा सोमवार को दायर किया गया। शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिका पर 10 जनवरी को शाम चार बजे नार्वेकर को फैसला सुनाना है। मध्यस्थ के रूप में विधान सभा अध्यक्ष, चाहे अधिकृत हो या अनौपचारिक, मु यमंत्री से उनके घर पर दो बार मुलाकात कर चुके हैं। यानी वे आरोपियों से दो बार मिल चुके हैं. हमारी नजर में वे आरोपी हैं। हमने उनके खिलाफ अयोग्यता का मामला दायर किया है। हम नॉर्वेवासियों से न्याय की उ मीद करते हैं।

प्रमुख समाचार

भारत में सामने आए कोविड के 475 नए मामले, 6 मौतें दर्ज

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि देश में मंगलवार को बीते 24 घंटों में 475 नए कोविड-19 मामले सामने आए और छह मौतें हुईं। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 6 नई मौतें कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और असम में हुईं। सोमवार को केरल, कर्नाटक और त्रिपुरा में कुल चार मौतें हुईं। इस बीच, एक्टिव मामलों की कुल संख्या सोमवार के 4,002 से गिरकर 3,919 हो गई।

अब तक, जनवरी 2020 में शुरुआती प्रकोप के बाद से भारत में कोरोनो वायरस मामलों की कुल संख्या 4,50,19,214 तक पहुंच गई है, जबकि, कुल मृत्यु का आंकड़ा 5,33,402 हो गया है। नया जेएन.1 सब-वेरिएंट, जिसे बीए.2.86 या पिरोला के नाम से जाना जाता है, केरल इस मामले की रिपोर्ट करने वाला पहला राज्य है। ओमिक्रॉन स्ट्रेन का जेएन.1 सबवेरिएंट तेजी से महाराष्ट्र राज्य में प्रमुख वेरिएंट बन गया है। जनवरी से कोरोना वायरस नमूनों पर हाल के जेनेटिक स्टडीज से पता चलता है कि राज्य में लगभग सभी मामलों के लिए जेएन.1 सबवेरिएंट जिम्मेदार है।

शाजापुर में अक्षत वितरण फेरी पर पथराव, धारा 144 लागू

शाजापुर। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में सोमवार की शाम को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अक्षत वितरण के लिए निकल रही शाम की फेरी पर कुछ सामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। तनाव बढ़ने के बाद तीन थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा 144 लागू कर दी गई है।

इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। सोमवार की शाम को अक्षत वितरण के लिए सायं फेरी निकाली जा रही थी, यह फेरी जब मोती मस्जिद के सामने से गुजरी थी तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए वहीं कुछ लोगों को चोटें भी आए हैं।

पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण बन गए और हिंदूवादी संगठनों ने थाने पहुंचकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। पथराव के बाद बाजार बंद कर दिए गए और भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। वही एहतियाती तौर पर मगरिया, काछीवाड़ा और लालपुर क्षेत्र में निषेधाज्ञा 144 लागू कर दी गई है।

उद्धव गुट के विधायक और सहयोगियों के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी

मुंबई। मुंबई के जोगेश्वरी में एक होटल के निर्माण के मामले में उद्धव गुट के नेता और विधायक रवींद्र वायकर और उनके सहयोगियों से संबंधित 7 स्थानों पर ईडी के छापे चल रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शहर के जोगेश्वरी इलाके में एक लग्जरी होटल के निर्माण में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के एक मामले में शिवसेना (यूबीटी) के विधायक रवींद्र वायकर और उनसे जुड़ी कुछ इकाइयों के परिसरों पर मंगलवार को छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एजेंसी मुंबई में करीब सात स्थानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि इनमें वायकर और उसके कुछ सहयोगियों तथा अन्य के परिसर भी शामिल हैं। वायकर (64) उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट से शिवसेना के विधायक हैं और महाराष्ट्र विधानसभा में जोगेश्वरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की प्राथमिकी से उपजा है, जिसमें विधायक पर एक बगीचे के लिए आरक्षित भूखंड पर एक पांच सितारा होटल के निर्माण के लिए अवैध रूप से मंजूरी प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि इस डील से बीएमसी को भारी नुकसान हुआ।

दुनिया भर में भारत की भावना का प्रतीक हैं प्रवासी : मोदी

नई दिल्ली। इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) पर 32 मिलियन से अधिक मजबूत भारतीय प्रवासियों की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूरे विश्व में विश्व, एकता और विविधता की भारत की भावना को बढ़ावा देने व उसको मूर्त रूप देने के लिए उनकी सराहना की। हर साल 9 जनवरी को मनाया जाने वाला यह दिन राष्ट्र के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान का सम्मान करता है, और 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में महात्मा गांधी की वापसी की याद भी दिलाता है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा,प्रवासी भारतीय दिवस पर शुभकामनाएं। यह दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों के योगदान और उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है। हमारी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने के प्रति उनका समर्पण सराहनीय है। वे दुनिया भर में एकता और विविधता की भारत की भावना का प्रतीक हैं। इस बीच, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

केरल के युवा कांग्रेस प्रमुख राहुल ममकूटथिल गिरफ्तार

तिरुवनंतपुरम। केरल पुलिस द्वारा मंगलवार को राज्य युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल ममकूटथिल को केरल के पथानामथिट्टा जिले में अदूर के पास उनके घर से गिरफ्तार किए जाने के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उन्हें यहां कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन से जुड़े पुलिस अधिकारियों की एक टीम ले गई। राज्य भर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

ममकूटथिल की मां ने आज सुबह-सुबह उनके घर पर पुलिस के पहुंचने के तरीके पर हैरानी व्यक्त की। ममकूटथिल की मां ने कहा, उन्होंने कॉलिंग बेल नहीं बजाई बल्कि सीधे मेरे घर में घुस आए। वहां काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। गिरफ्तारी का कारण जानने की मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे उच्च अधिकारियों से आदेश ले रहे हैं और उसे अपने साथ ले गए। यह गहरी चिंता का विषय है क्योंकि मेरा बेटा ही सही तरीके से राजनीति करता है। उसे ऐसे ले जाया गया जैसे उसने कोई जघन्य अपराध किया हो सूत्रों के अनुसार, पिनाराई विजयन सरकार की मनमानी के खिलाफ पिछले महीने राज्य की राजधानी में युवा कांग्रेस की एक विशाल विरोध रैली के बाद एक आरोपी के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

कश्मीर पर अमित शाह की रणनीति का इंतजार

अभय कुमार दुबे

कश्मीर की संवैधानिक हैसियत बदलने के लिए केंद्र सरकार ने अपना ऐतिहासिक हस्तक्षेप उस दौरान किया था जब वहां की पारंपरिक राजनीतिक शक्तियों की साख पूरी तरह से गिर चुकी थी। पीपुल्स डेमाक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ सरकार चलाने से हुए राजनीतिक नुकसान से उबरने में नाकाम थी। लोकसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती समेत उसके सभी उम्मीदवार उस दक्षिण कश्मीर में चुनाव हार गए थे जो कुछ दिन पहले उनका गढ़ हुआ करता था। नेशनल कांफ्रेंस की हालत यह थी कि चुनाव में कुछ सकारात्मक परिणाम मिलने के बावजूद उसकी सांगठनिक हालत खस्ता दिखाई दे रही थी। अब्दुल्ला परिवार के नेतृत्व की चमक पहले जैसी नहीं रह गई थी। फारुक अब्दुल्ला भ्रष्टाचार के मामलों में बुरी तरह से फंसे हुए थे, और उमर अब्दुल्ला ने कोई पंद्रह दिन पहले ही कार्यकर्ताओं के बीच जाना शुरू करके अपनी निष्क्रियता तोड़ी थी। कांग्रेस का संगठन घाटी में पहले ही ठंडा पड़ा था।

दरअसल, केंद्र पहले ही इस स्थिति को भांप चुका था। कश्मीर के जानकार मानते हैं कि भाजपा सरकार ने एक तिहरी रणनीति बनाई। एक तरफ तो उसने भाजपा की घाटी में उपस्थिति बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सदस्यता भर्ती अभियान चलाना शुरू किया। अगर भाजपा के दावों पर भरोसा किया जाए तो उसने दो महीनों में ही कोई 85000 सदस्य केवल घाटी से ही भर्ती कर लिये थे। हो सकता है कि यह आंकड़ा कुछ बढ़ा-चढ़ा हो, लेकिन फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा मुस्लिम बहुल घाटी में अपने कदम मजबूत करने में लगी हुई थी ताकि केंद्र शासित विधानसभा के चुनाव में कम से कम आठ-दस सीटें जीत सके। भाजपा की गतिविधियों को ध्यान से देखने वाले समझ रहे हैं कि घाटी के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां भाजपा की संभावनाएं परवान चढ़ सकती हैं। जैसे बड़गाम जिला है जो शिया बहुल आबादी वाला है। हम जानते हैं कि शिया मुसलमान सत्तर के दशक से ही पहले जनसंघ और अब भाजपा के प्रति हमदर्दी रखते हैं। ध्यान रहे कि अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र के त्राल विधानसभा क्षेत्र (जो सर्वाधिक आतंकवाद-पीड़ित है) में भाजपा को नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे। भाजपा तो यह भी मानती है कि अगर घाटी से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों को वोट डालने के लिए एम फॉर्म भरने के जटिल झंझट से न गुजरना पड़ता तो फारूक अब्दुल्ला तक को चुनाव में हराया जा सकता था।

दूसरी तरफ केंद्र ने पहले से ही घाटी में नई राजनीतिक शक्तियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। आईएएस में आकर नाम कमाने वाले शाह फैजल के नेतृत्व में एक पार्टी बनवा दी गई थी। विधानसभा में भाजपा विधायकों के हाथों जिन इंजीनियर रशीद का मुंह काला किया गया था, उनकी पार्टी भी अपना काम कर रही थी। उन्होंने फैजल की पार्टी के साथ मिल कर गठजोड़ बना लिया था। रशीद स्थानीय अखबारों में पहले से मोदी समर्थक लेख लिख कर घाटी के बारे में कोई असाधारण कदम उठाने की अपीलें कर रहे थे। इस दुतरफा रणनीति का मतलब यह निकलता था कि निकट भविष्य में जब नेतागण रिहा किए जाते तो घाटी में होने वाली राजनीतिक गोलबंदी एकतरफा भारत-विरोधी नहीं होती।

तीसरे, भाजपा विधानसभा के ऊपर से घाटी का प्रभुत्व घटाने की जुगाड़ में थी. विधानसभा में कुल 87 सीटें थीं जिनमें 46 घाटी के, 37 जम्मू के और 4 लद्दाख के हिस्से की थीं। जाहिर है कि घाटी में जीतने वाला कश्मीर पर हुकूमत करता था। ऐसा लगता है कि इस समीकरण को बदलने के लिए सरकार दो विधियां अपना सकती थी। पहली, परिसीमन आयोग बना कर जम्मू क्षेत्र की सीटों की संख्या कुछ बढ़ाई जा सकती थी (क्योंकि जम्मू की जनसंख्या घाटी से अधिक है)। दूसरी, पाक अधिकृत कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाली 24 सीटें फ्रीज पड़ी हुई थीं। इनमें से कुछ सीटें इस चतुराई के साथ डिफ्रीज की जा सकती थीं कि उनका लाभ भी भाजपा को मिले। विश्लेषकों को लग रहा था कि उस समय तक विधानसभा चुनाव टाले जाते रहेंगे जब तक सीटों का यह समीकरण भाजपा के अनुकूल नहीं हो जाता।

अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र के कश्मीर संबंधी फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है इसलिए अब यह सही मौका है कि केंद्र सरकार बिना देर किए कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करे। परिसीमन भी हो चुका है। अमित शाह ने संसद में परिसीमन से बनी नई परिस्थिति भी खोल कर रख दी है। जम्मू के हिस्से में आने वाली 37 सीटें अब बढ़ कर 43 हो चुकी हैं। कश्मीर की 46 सीटों में केवल एक का ही इजाफा हुआ है। पाक कब्जे वाले कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए 9, कश्मीर के विस्थापितों के लिए 2, कब्जे वाले कश्मीर के विस्थापितों के लिए 1 और नामजदगी के लिए 5 सीटों का प्रावधान किया गया है। जाहिर है कि केंद्र ने अपनी शतरंज बिछा दी है. ऊपर से खिलाड़ी केवल एक ही है। उसे ही शह देनी है, और उसे ही मात देनी है। बाकी खिलाड़ी काफी हद तक निष्प्रभावी पड़े हुए हैं।

क्रॉस फायरिंग की जांच करने मुतवेंडी गांव नहीं पहुंच पाई कांग्रेस की टीम

मौत की गोली किसकी थी? आदिवासियों पर अत्याचार के आरोप

बीजापुर। क्रॉस फायरिंग में 6 माह की मासूम की मौत पर उपजे सवालों के जबाव तलाशने छत्तीसगढ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार विधायक विक्रम मंडावी के नेतृत्व में कांग्रेस का 5 सदस्यीय जांच दल मुतवेंडी गांव नहीं पहुंच सका। विधायक विक्रम के मुताबिक सुरक्षा कारणों और पहुंच मार्ग पर जहां-तहां आईईडी मौजूद होने की आशंका से सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें और उनकी टीम को मुतवेंडी जाने से रोका।

बता दें कि, आला अधिकारियों से लंबी चर्चा के बाद दल को कांवड़गांव जाने की इजाजत मिली। जहां मुतवेंडी समेत आसपास के गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में जुटे थे, जो अपनी बात रखना चाहते थे। जांच दल के सदस्यों ने कुछ चश्मदीदों से बात की। उनका बयान दर्ज किया। चश्मदीदों की मानें तो घटना जहां हुई तब वे मौके पर थे। गोली चलने की आवाज सुनते वे सब इधर-उधर अपनी जान बचाने भागे। गोलीबारी थमी तो पाया कि, बच्ची को गोली लगी है। तभी सुरक्षा बल के जवान भी वहां पहुंच गए। मौके पर नक्सली थे, नक्सलियों की तरफ से गोली चली थी या जवानों की तरफ से यह तो जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा। जानकारी के अनुसार, जांच दल की मुलाकात मृत बच्ची की मां से नहीं हो सकी है। जांच दल उनसे भी मुलाकात करेगा।

विधायक के अनुसार, भाजपा के सत्तासीन होते साथ ही आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं में इजाफा हुआ है। जांच दल जिस इलाके का दौरा कर लौटा है, वहां ग्रामीण डरे-सहमे हुए हैं। वहां ग्रामीण सुरक्षा बलों की बर्बरता का शिकार हो रहे हैं।

एड़समेटा, सारकेगुड़ा पीड़ितों के सवाल पर विक्रम ने कहा कि, सरकार किसी की भी न्याय मिलना चाहिए। एड़समेटा, सारकेगुड़ा बड़ी घटनाएं हैं, कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में एड़समेटा की न्यायिक जांच रिपोर्ट को विस के पटल पर रख चुकी है। अब होना यह चाहिए कि, भाजपा सरकार रिपोर्ट को सार्वजनिक करते पीड़ितों को न्याय दें।

विधायक ने भाजपा पर उद्योगपतियों का साथ देने और आदिवासियों को जल-जंगल से बेदखल करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि, भाजपा के सत्ता में काबिज होते उद्योगपतियों को बढ़ावा मिलता है। हसदेव प्रकरण इसकी बानगी है। कांग्रेस किसी भी सूरत में कोल माइंस आवंटन के पक्ष में नहीं हैं।

कैम्प स्थापित करना केंद्र-राज्य सरकार का निर्णय

आदिवासियों से बर्बरता और सुरक्षा बलों के कैम्प विस्तार पर विधायक ने कहा कि यह केंद्र और राज्य सरकार का मसला है। कहां कैम्प बैठाना है और कहां नहीं बैठाना है, यह केंद्र और राज्य सरकारें तय करती है।

देशभर में ओपीएस की मांग को लेकर जारी क्रमिक हड़ताल का प्रदेश में भी दिखा असर

■ तीन दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे रेलवे कर्मचारी, एनपीएस गो बैक के लगाए नारे

महासमुंद। देशभर में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन के आव्हान पर रेलवे कर्मचारी आज जिला मुख्यालय के सहायक मंडल इंजीनियर कार्यालय के मुख्य गेट पर ओपीएस की बहाली को लेकर तीन दिवसीय भूख हड़ताल पर पर बैठ गए है, कर्मचारियों की मांग है कि, नई पेंशन नीति (एनपीएस) हटा कर पुरानी पेंशन नीति (ओपीएस) लागू किया जाए।

श्रमिक यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि, केन्द्र सरकार नई पेंशन नीति को हटाकर पुरानी पेंशन नीति जब तक लागू नही करता तब तक कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल पर बैठे कर्मचारी एनपीएस गो बैक के नारे लगा रहे है। बता दें कि, 8 जनवरी से शुरु हुआ यह प्रदर्शन 10 जनवरी तक जारी रहेगा अगर इस दौरान मांगे पूरी नहीं होती तो ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन के निर्णय के अनुसार आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

बता दें कि, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, संगठनों एवं प्रतिष्ठानों के सामने आठ जनवरी से 11 जनवरी तक 'रिले हंगर फास्ट' का आह्वान किया गया है। इस दौरान विभिन्न कर्मचारी संगठन, भूखे रह कर सरकार से 'पुरानी पेंशन बहाली' की मांग करेंगे। शुक्रवार को नई दिल्ली के स्टेट एंट्री रोड स्थित एआईआरएफ कैंपस की जेपी चौबे मेमोरियल लाइब्रेरी में आयोजित पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच (जेएफआरओपीएस) के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जल्द ही कोई तिथि निर्धारित करने पर सहमति हुई है। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए), की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव सी। श्रीकुमार का कहना है, स्ट्राइक नोटिस और अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि तय होने के बाद सरकार को अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी को जेएफआरओपीएस के निर्णयों की जानकारी देने के लिए पत्र जारी होगा।

वहीं ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद 'जेसीएम' के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा है कि, रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96 फीसदी कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग (सिविल) के चार लाख कर्मियों में से 97 फीसदी कर्मी, हड़ताल के पक्ष में हैं। शुक्रवार को ज्वाइंट फोरम की बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए निर्धारित तिथि की घोषणा करने पर सहमति बन गई है। पहले चरण में सरकारी कर्मचारी, भूखे रहकर केंद्र सरकार को चेताएंगे। उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि घोषित की जाएगी।

त्रिकुंडा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप कलेक्टर से ग्रामीणों ने की शिकायत

ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों को डराने-धमकाने की कोशिश

बलरामपुर। रामचंद्रपुर विकासखंड के त्रिकुंडा ग्राम पंचायत में अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है। सरपंच, उपसरपंच और सचिव के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट जाकर शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में मनरेगा के तहत साल 2020 से 2023 तक के बीच फर्जी मस्टर रोल में फर्जी हाजिरी भरी गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से दो-दो हजार रुपए तक वसूले गए। पंचायत में वर्ष 2023 में छठ घाट निर्माण निर्माण के नाम पर राशि का बंदरबांट कर भ्रष्टाचार किया गया। जिसके बाद शासकीय मद के पैसों का गबन किया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अनियमितता की जांच करने और कार्रवाई करने की मांग की है।

शौचालय निर्माण में हुई गड़बड़ी

ग्रामीणों की माने तो त्रिकुंडा ग्राम पंचायत में केन्द्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत 2017-18 के दौरान शौचालय का निर्माण कार्य कराने के नाम पर भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया। ज्यादातर शौचालय निर्माण या तो सिर्फ कागजों पर ही हुए या फिर आधा-अधूरा ही निर्माण हो सका है।

ग्राम सभा के दौरान पंचायत में हुए अनियमितता और भ्रष्टाचार का मुद्दा ग्रामीणों ने जब उठाया तो उन्हें धमकी मिली। सचिव, सरंपच और उप सरपंच ने ग्रामीणों को डरा धमकाकर मामला दबाने की कोशिश की। लेकिन ग्रामीणों ने धमकी से बिना डरे कलेक्टोरेट जाकर इस मामले की शिकायत सीधा कलेक्टर से की है। जिसके बाद अब कलेक्टर ने अफसरों को आरोपों के जांच करने के लिए कहा है।

सुकमा में बड़ी नक्सली घटना की थी साजिश जवानों ने बरामद किया 15 किलो का आईईडी

सुकमा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अंदरूनी इलाकों में जैसे जैसे कैंप खोले जा रहे हैं नक्सलियों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। नक्सली जवानों को नुकसान पहुंचाने जगह जगह आईईडी प्लांट कर रहे हैं। सुकमा में पोटकापल्ली के पास नक्सलियों द्वारा लगाया गया 15 किलो का आईईडी बरामद किया गया है। किस्टाराम थाना क्षेत्र के कैंप पोटाकपल्ली से संयुक्त अभियान पर निकले 212 बटालियन सीआरपीएफ और जिला बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाया गया था।

सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि सुकमा जिले के किस्टारम थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किए गए पोटकपल्ली कैंप से 212 वाहिनी सीआरपीएफ और जिला बल के जवानों को सर्चिंग के लिए आसपास के क्षेत्र में रवाना किया गया था। सर्चिंग के दौरान पोटकपल्ली कैंप से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बम को जवानों बरामद किया। जो करीब 15 किलोग्राम वजनी था। इसके बाद जवानों ने सूझबूझ और सतर्कता से आईईडी बम को सुरक्षित तरीके से मौके पर ही नष्ट कर दिया और नष्ट करने का लाइव वीडियो भी मोबाइल कैमरे में कैद किया गया है।

सोमवार को बीजापुर में भी जवानों ने 5 किलो का आईईडी बरामद किया था। डीआरजी, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ के जवान चेरपाल और गंगालूर के बीच सर्चिंग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान मेन रोड पर जवानों को 5 किलो का आईईडी मिला। जवानों ने तुरंत बीडीएस टीम को बुलाया और आईईडी डिफ्यूज करवाया। आईईडी प्रेशर स्विच सिस्टम के जरिए जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाया गया था।

इससे पहले 7 जनवरी को भी जवानों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरते हुए धर्मारम और चिंतावागु नदी के बीच 5 किलो और 8 किलोग्राम के दो आईईडी बरामद किये थे। जिसके बाद उन्हें नष्ट किया गया। शनिवार को भी जवानों ने 3-3 किलो के 2 आईईडी बरामद किए थे।

हाथी बौराया, खाने की तलाश में घर को किया धराशाई

दबने से महिला की हुई मौत, बच्ची घायल

जशपुर। पत्थलगांव के डुमरबहार गांव में एक हाथी ने बीती रात घरों में तोड़-फोड़ करते हुए जमकर उत्पात मचाया। हाथी की तोड़-फोड़ के दौरान घर पर मौजूद सदस्य जान बचाकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन एक महिला की मलबे में दबने से मौत हो गई, वहीं एक बच्ची घायल हो गई।

घर की तोड़-फोड़ से मलबे में दबकर सुहानी बाई की मौत हो गई, जिस पर वन विभाग ने मृत महिला के परिजनों को तत्काल 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। वहीं पत्थलगांव इलाके में हाथियों के उत्पात की सूचना मिलते ही डीएफओ सहित वन अमला रात को ही मौके पर पहुंच गया। लेकिन हाथी तमाम कवायदों के बाद भी गांव से निकलने का नाम नहीं ले रहा था।

केवल डुमरबहार ही नहीं बल्कि दूसरे गांव में भी हाथियों का दल तोड़ -फोड़ कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हालांकि, वन विभाग का अमला ने 30 प्रभावित गांवों में 24 घंटे निगरानी का काम शुरू कर दिया है। रात को वनकर्मी मशाल लेकर तथा गांव-गांव में कोटवार भी हांका लगाकर लोगों को लगातार सतर्क कर रहे हैं।इसके बावजूद भोजन की तलाश में हाथी घरों को क्षतिग्रस्त कर दे रहे हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कुलपति को धमकी भरा पत्र भेजने वाला निकला भृत्य

बिलासपुर। पंडित सुंदर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति को साधारण डाक से धमकी भरा पत्र भेजने वाले को कोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी विश्वविद्यालय में भृत्य है। पुलिस के अनुसार 19 दिसम्बर 2023 को पंडित सुंदर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बंश गोपाल सिंह को एक साधारण डाक से धमकी भरा पत्र मिला था। फर्जी नाम व पता लिखकर आरोपी ने धमकी भरे पत्र में पुत्र को जान से मारने की धमकी देते हुए वेतन बढ़ाने, नई भर्ती पर रोक लगाने सहित गालीगलौज लिखा था। कुलपति की शिकायत पर कोनी पुलिस मामले की जांच कर रही थी। जांच के दौरान कोनी पुलिस ने विश्वविद्यालय पहुंच कर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का पिछले एक साल के छुट्टी का आवेदन पत्रों को मंगाकर हस्तलिपि से मिलान कर रही थी। जांच के दौरान कोनी पुलिस को पता चला कि 6 माह पूर्व विश्वविद्यालय में कार्यरत भृत्य संतोष कुमार पाण्डेय ने कुलपति को नई भर्ती कैसे लोगे मैं देखता हूं कहकर धमकी भरा पत्र लिखा था।

वंदित जैन ने सीए फाइनल में हासिल किया 20वां रैंक

दुर्ग। दुर्ग निवासी सीए हर्ष जैन (सांखला) के पुत्र वंदित जैन ने सीए फाइनल एग्जाम में पूरे देश में 20वां स्थान प्राप्त कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। प्रथम अटेम्प्ट में ही वंदित ने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एक साथ पास कर ये कीर्तिमान रचा है। साथ ही उन्होंने सीएफए (यूएस) के भी दो लेवल उच्च अंकों से उत्तीर्ण किए हैं। वंदित ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता को दिया है। वंदित ने बताया कि महज 13 साल की उम्र से ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें सी.ए. बनना है। जिसके लिए उन्होंने शुरू से दृढ़ता और कड़ी मेहनत को अपनी सफलता तक पहुंचने का एक मात्र रास्ता माना। सुबह जैसे ही द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में रिजल्ट आया पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। छत्तीसगढ़ के समस्त सीए और अधिवक्ताओं द्वारा वंदित को फोन पर बधाई दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई।

धमतरी में ड्यूटी पर तैनात जवानों को डिग्री की ललक

धमतरी। जिले में पुलिस कर्मियों को डिग्री की ऐसी ललक लगी है कि ये अपनी ड्यूटी तक भूल गए और पढ़ाई में मशगूल हो गए। दरअसल, जिले में यातायात पुलिस के दो कर्मचारियों ने शिक्षा से लगाव की मिसाल पेश की है। एक सिपाही 13 साल बाद ग्रेजुएशन शुरू कर रहा है, तो एक हवलदार 21 साल बाद बीए का फॉर्म भर रहा है। दरअसल धमतरी यातायात डीएसपी खुद 8 डिग्रियां ले चुके हैं। अब वो 9वीं की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा के लिए अपने अफसर का जज्बा देख अब छोटे कर्मचारी भी डिग्री पाने के लिए ऑन ड्यूटी पढ़ाई कर रहे हैं। धमतरी में यातायात पुलिस में कॉन्स्टेबल गनपत डिंडोल्कर और हेड कॉन्स्टेबल कमल किशोर साहू इस साल कॉलेज की पढ़ाई शुरू करेंगे। कमल किशोर ने 21 साल पहले 12वीं के बाद पुलिस की नौकरी लगते ही पढ़ाई छोड़ दी थी। ऐसे ही गनपत ने भी 13 साल पहले नौकरी लगते ही 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी।ये दोनों अपने समय के मेधावी छात्र रहे हैं। लेकिन नौकरी लगने के बाद पढ़ाई को जरूरी नहीं समझा या यूं कहें कि पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला।

धमतरी में स्कूल बस को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर

धमतरी। शहर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सिहावा रोड में ट्रक और बस में सीधी टक्कर हुई है। जानकारी के अनुसार हादसे में लगभग 6 स्कूली बच्चे घायल हो गए। जिसमें से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि हादसे में निजी स्कूल की बस और ट्रक में टक्कर हुई है। विद्या कुंज स्कूल की बस बच्चों को लेते हुए दानीटोला चौक की ओर जा रही थी। इसी दौरान सामने से सीजी 05 डी 2111 तेज रफ्तार ट्रक वहां से गुजर रहे हाइवा को ओवरटेक करते हुए आ रही थी। तेज रफ्तार ट्रक ने जालमपुर मोड़ में सिहावा रोड के पास सामने से आ रही स्कूल बस को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चीख पुकार मच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी थी आस पास के लोगों को बम ब्लास्ट होने जैसा महसूस हुआ। बताा जा रहा है कि बच्चे परीक्षा देने स्कूल जा रहे थे। घटना के बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना स्कूल प्रबंधन को दी। स्कूल बस का एक्सीडेंट होने की खबर लगते ही स्कूल में हड़कंप मच गया। परिजनों को फोन कर इसकी सूचना दी गई।

बीमारी का बहाना बनाकर युवक से 42 लाख की ठगी

बिलासपुर। बिलासपुर में महिला ने बीमारी का बहाना बनाकर एक युवक के साथ 42 लाख रुपए की ठगी की है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब युवक को रुपए की जरुरत पड़ी और वो महिला से पैसे मांगने उसके घर गया। महिला ने युवक को देखते ही बहाने बनाने शुरु कर दिए।आखिरकार युवक को शक हुआ कि उसके पैसे अब फंस चुके हैं। लिहाजा युवक ने थाने सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत की। सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रदीप आर्या ने बताया कि सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया के रहने वाले रविंद्र सिंह भाटिया से अन्नपूर्णा नाम की महिला की मुलाकात हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई। इसके बाद पारिवारिक रिश्ते भी बने। कोविड काल के दौरान महिला अपने परिचित डॉक्टर के साथ 10 नवंबर 2020 को युवक की कंपनी में पहुंची। इसी दौरान महिला ने बताया कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है। उनके बेहतर इलाज के लिए रकम की जरूरत है। रविंद्र ने अन्नपूर्णा की बातों में आकर उसके खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए।

धान खरीदी केंद्र में किसानों का धरना प्रभारी पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप

कोरबा। कोरबा के ग्राम तिलकेजा स्थित धान खरीदी केंद्र में उस वक्त विवाद की स्थिती निर्मित हो गई जब प्रभारी ने पांच किसानों को यह कहकर चलता कर दिया कि उनका धान अमानक है। बस इसी बात को लेकर किसान आक्रोशित हो गए और केंद्र के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। किसानों ने प्रभारी पर दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। इस संबंध में जब हमने प्रभारी से बात की तब उन्होंने अपने उपर लगे आरोप को सिरे से नकार दिया।

धान खरीदी केंद्र में एक किसान ने फड़ प्रभारी पर केंद्र में घुसने नहीं देने का आरोप भी लगाया। किसान ने बताया कि जब वह अपना धान लेकर भीतर घुसा तब गेट बंद कर दिया गया और उसके साथ धक्का-मुक्की की गई जिससे वह जमीन पर गिर गया जिससे उसके हाथ के अंगूठे में चोट भी लगा है।

किसान शंकर दयाल शर्मा ने बताया कि धान का टोकन काटने के बाद बेचने के लिए आया हुआ था इसके बाद गेट खुलने के बाद जैसे ही अंदर गया उसके साथ प्रभारी के द्वारा दूर्व्यवहार किया गया जब इसका विरोध किया गया तब उसने धन लेने से मना कर दिया।

किसानों के प्रदर्शन से विवाद की स्थिती निर्मित हो गई लिहाजा पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। उरगा थाना प्रभारी युवराज तिवारी ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए लोगों को समझाया गया जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। काफी समझाने के बाद विवाद समाप्त हुआ और किसानों ने धरना समाप्त किया।

फिर से हड़ताल की राह पर ड्राइवर, रात से स्टेरिंग छोड़ो आंदोलन होगा शुरू

कबीरधाम। कबीरधाम जिले में एक बार फिर से वाहन चालकों की हड़ताल शुरू होने वाली है। इसे लेकर मंगलवार को कबीरधाम में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष राजेश श्रीवास ने बताया कि सभी ड्राइवर सरकार द्वारा बनाए गए हिट एट रन के कानून, जिसमें दस साल की सजा का प्रावधान है, इस कानून की वजह से हमे गाड़ी चलाने में डर लगने लगा है। इसलिए सभी ड्राइवर नौ जनवरी से लेकर जब तक यह कानून नहीं हट जाता, तब तक स्वयं अपनी मर्जी से स्टेरिंग छोड़ो आंदोलन के तहत काम पर नहीं जाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने कहा कि हम चक्काजाम या हड़ताल जैसे कदम नहीं उठा रहे हैं, अपनी मर्जी से काम पर नहीं जा रहे हैं। विचार विमर्श के लिए अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। अन्य राज्यों/जिलों से आने वाले ड्राइवरों से चर्चा करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से स्टेरिंग छोड़ो आंदोलन के माध्यम से हल निकालना चाहते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति आंदोलन के तहत किसी प्रकार की उपद्रव या शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उस व्यक्ति की स्वयं जवाबदारी रहेगी। संगठन या पदाधिकारी जवाबदार नहीं रहेगा।

सरकारी स्कूल पहुंचा बुलडोजर, पंचायत सचिव ने अतिक्रमण कर बना लिया था मकान

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है। सोमवार को प्रशासन का बुलडोजल बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत बरतीखुर्द पहुंचा। यहां सरकारी स्कूल में ही अवैध अतिक्रमण किया गया था। सरकारी स्कूल में कब्जा कर पंचायत सचिव ने मकान बना लिया था।

बरतीखुर्द के प्राइमरी और मिडिल स्कूल परिसर में लंबे समय से एक पंचायत सचिव ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। सचिव ने स्कूल परिसर में ही अपना मकान बना लिया और उसमें परिवार के साथ रहने लगा। इस बात का विरोध लगातार गांव वालों ने किया लेकिन पंचायत सचिव किसी की नहीं सुनते हुए अपनी ही चला रहा था। गांव के लोगों और पंचायत के दूसरे लोगों ने इसकी शिकायत तहसीलदार से की। मामला तहसील न्यायालय भी पहुंचा।

तहसील न्यायालय में सरकारी स्कूल में अतिक्रमण का मामला पहुंचने के बाद कई बार पंचायत सचिव को नोटिस भेजा गया। लेकिन ना तो वह नोटिस ले रहा था ना ही उसका जवाब दे रहा था। इसके बाद न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत वाड्रफनगर तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला दलबल के साथ बरतीखुर्द स्कूल पहुंचा और पंचायत सचिव के मकान को तोड़कर स्कूल को अतिक्रमण मुक्त कराया।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री साय ने भूपेश के दिवंगत पिता नंदकुमार बघेल को दी श्रद्धांजलि

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पाटन

सदन पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिवंगत पिता नंदकुमार बघेल के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री साय ने पूर्व मुख्यमंत्री बघेल एवं उनके परिजनों से भेंटकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से उनके परिवारजनों को इस असीम दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ। रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण सिंहदेव ने भी दिवंगत नंदकुमार बघेल को श्रद्धांजलि दी।

किसान क्रेडिट कार्ड से मत्स्य कृषकों को मिल रही सब्सिडी

रायपुर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिले में संकल्प शिविर लगातार आयोजित किये जा रहे हैं। साथ ही शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही और योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही भी अपनी कहानी अपनी जुबानी बता रहे हैं। इन्हीं हितग्राहियों में हैं ऐसे मत्स्य किसान, जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मछली पालन के लिये मिले सब्सिडी का लाभ लेने वाले धमतरी जिले के तरसींवा गांव के महेन्द्र कुमार, भोथीपार की श्रीमती खिलेश्वरी सेन सहित आठ अन्य मत्स्य कृषक। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय योजना से मछली पालन के लिये मिलने वाली सब्सिडी से लाभ लेकर वे आर्थिक स्थिति को सुधारकर प्रगति की राह में अग्रसर हो रहे हैं। गौरतलब है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पट्टाधारक अथवा स्वयं की भूमि में निर्मित तालाब एवं संवर्धन पोखर हेतु प्रति हेक्टेयर चूना, मत्स्यबीज, मत्स्यपूरक आहार, दवाईयां एवं अन्य के लिये एक लाख 50 हजार रूपये के मान से ऋण दिया जाता है।

बसवराजू एस होंगे मुख्यमंत्री के सचिव

रायपुर। राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक

सेवा के अधिकारी श्री बसवराजू एस. की पदस्थापना सचिव, मुख्यमंत्री के रूप में की गई है।उन्हें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया।

कमलादेवी संगीत महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव 11 जनवरी को

रायपुर। भातखंडे ललितकला शिक्षा समिति द्वारा संचालित कमलादेवी संगीत महाविद्यालय(गुरुकुल काम्पलेक्स) में वार्षिकोत्सव -2024 का आयोजन 11 जनवरी को किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक पुरंदर मिश्रा,अध्यक्षता भातखंडे ललितकला शिक्षा समिति के अध्यक्ष तरल मोदी व विशेष अतिथि होंगे भातखंडे ललितकला शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अजय तिवारी। कार्यक्रम शाम 5 बजे रंगमंदिर गांधी चौक में आयोजित है। दूसरे दिन 12 सितंबर को स्टूडेंट डे मनाया जायेगा जिसमें विद्यार्थियों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जायेंगे।

आरडी तिवारी आत्मानंद स्कूल का गिरा छत का प्लास्टर, बाल-बाल बचे बच्चे

रायपुर। शहर के आरडी तिवारी स्वामी आत्मानंद स्कूल के छत का प्लास्टर गिर गया है। इस दौरान वार्षिक उत्सव की तैयारी कर रहे स्कूली बच्चे बाल-बाल बचे हैं। एक बड़ा टल गया है। घटना में किसी को चोट नहीं आई है। वहीं प्लास्टर गिरने से हड़कंप मच गया है। अंदर बाहर से चमाचम दिखाने की कोशिश रंग पेंट से भरपूर की गई है लेकिन गुणवत्ता पर सवालिया निशान लग गया है। ट

रायपुर पुलिस का हुड़दंगियों पर एक्शन, मचाया उत्पात

रायपुर। रायपुर पुलिस का बदमाशों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है, बीती रात शहर के भनपुरी इलाके के वार्ड क्रमांक चार में उत्पात मचाने वाले हुड़दंगीयों को पुलिस ने न सिर्फ 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया बल्कि जहां उन्होंने दहशत फ़ैलाने की कोशिश की वहीं पर उनका जुलुस निकाला, ताकि गुंडे बदमाशों को ये मैसेज जा सके की, रायपुर पुलिस किसी भी हाल में उन्हें बख्शाने वाली नहीं है.

बीती रात राजधानी के भनपुरी इलाके में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया, लाठी-डंडे से लैस 30 से 35 युवकों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की. इस घटना के बाद इलाके में माहौल गरमा गया और बदमाशों के उत्पात से आक्रोशित स्थानीय रहवासियों ने खमतराई पुलिस थाने का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, रहवासियों ने ये भी आरोप लगाया कि, युवकों ने युवतियों और महिलाओं से भी छेड़छाड़ की है.

थाना परिसर में लोगों की भारी भीड़

जमा होने की सूचना पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर शांत कराया और आरोपियों की तलाश में जुट गई.

इसी दौरान साइबर सेल और खमतराई थाने की संयुक्त टीम को जानकारी मिली की इस उत्पात के मास्टरमाइंड पंकज कुशवाहा और इंद्रजीत सिंह रायपुर से भागने की फ़िराक में है और रायपुर रेलवे स्टेशन में मौजूद है. जिसके बाद दोनों की घेराबंदी कर पुलिस ने उन्हें रेलवे स्टेशन में ही धर दबोचा.

पुलिस की पूछताछ में पंकज कुशवाहा और इंद्रजीत सिंह ने उत्पात में उनका साथ देने वालों के नाम उगले, जिसके बाद पुलिस ने एक-एक कर 19 युवकों को गिरफ्तार किया और जहां उन्होंने दहशत फ़ैलाने की कोशिश की वहीं पर उनका जुलुस निकला, ताकि गुंडे बदमाशों को ये मैसेज जा सके की रायपुर पुलिस किसी भी हाल में बदमाशों को छोड़ने वाली नहीं है. 6 टीआई और सीएसपी की मौजूदगी में आरोपियों का यह जुलुस निकला गया.

गौरतलब है कि, कल रात कि इस घटना से भनपुरी में माहौल गरमाया हुआ है, वहीं अभी भी कई हुड़दंगी फरार है, जिनकी तलाश जारी है, पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों के खिलाफ बलवा, मारपीट, गाली-गलौज समेत कई धाराओं में अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. वहीं सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि, घटना के विरोध में स्थानीय रहवासियों ने कथित तौर पर आज भनपुरी बंद का आह्वान किया है.

नगर पंचायत मारो में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, पार्षदों ने कलेक्टर को सौंपा आवेदन

बेमेतरा। 15 पार्षदों वाले नगर पंचायत मारो में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।आवेदन में उपाध्यक्ष आराधना सिंह राजपूत समेत 12 पार्षदों ने हस्ताक्षर किया है।जिसमें 6 पार्षद कांग्रेस समर्थक और 5 पार्षद बीजेपी समर्थक हैं। वहीं 1 पार्षद निर्दलीय है। कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन में नगर पंचायत मारो के पार्षदों ने अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

मारो नगर पंचायत के पार्षदों ने अध्यक्ष पर काम को ठीक ढंग से नहीं करने का आरोप लगाया है। नगर पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल में वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, श्रद्धांजलि राशि जैसी योजनाओं का फायदा हितग्राहियों को नहीं मिल सका है। नगर पंचायत मारो में मूल बहुत सुविधा बिजली पानी स्वच्छता का अभाव है। वहीं अनिमितता के कारण लाखों रुपए की क्षति हुई है। साथ ही अध्यक्ष पर पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार करने की बात सामने आई है।

सरकार बदलने के बाद नगरी निकायों में जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं। उसका डर नवागढ़ जनपद पंचायत में भी देखा जा रहा है। जहां कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष अंजली सतीश मार्कंडेय ने कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक दयाल दास बघेल से मुलाकात की है। वहीं अभी देखना होगा कि 12 जनवरी को जनपद पंचायत में कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल समीक्षा बैठक लेंगे। इस दिन बड़ी उलट - पुथल की संभावना जताई जा रही है।

विधानसभा सत्र में ऑनलाइन प्रश्न पूछने विधायकों को दिया गया प्रशिक्षण

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधान सभा के सभी नव निर्वाचित विधायकों के द्वारा आगामी बजट सत्र, 2024 के प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा हेतु सोमवार को विधानसभा स्थित मुख्य समिति कक्ष में एनआईसी रायपुर के तकनीकी सहयोग से विधायकों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया।

इस प्रशिक्षण सत्र में, विधायकों को ऑनलाइन प्रश्नों की सूचनाएं प्रस्तुत करने से संबंधित सैद्धांतिक और व्यावहारिक विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। नवनिर्वाचित विधायक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र में शामिल हुए। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने प्रशिक्षण सत्र की

अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष

के मार्गदर्शन में नवनिर्वाचित सदस्यों की सुविधा हेतु विधान सभा सचिवालय की पेपर लेस कार्यप्रणाली, पर्यावरणीय महत्व के इस सशक्त कदम की षष्ठम विधान सभा में भी अनवरत जारी रहने की जानकारी दी। विधान सभा सचिव दिनेश शर्मा द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस प्रशिक्षण सत्र के अतिरिक्त सदस्यों की सुविधा के लिए ऑनलाइन प्रश्नों की सूचनाएं प्रस्तुत करने हेतु विधान सभा की वेबसाइट पर संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन वीडियो, सरल शब्दों में एक पृथक संक्षिप्त वीडियो, दिशानिर्देश एवं एक हेल्प मैनुअल भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से सदस्य सरलता पूर्वक अपने अपने विधान सभा क्षेत्र या गृह स्थान से ही निर्धारित तिथि एवं समय पर बिना रायपुर विधान सभा आए ऑनलाइन अपने प्रश्नों की सूचनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस प्रशिक्षण सत्र के समापन अवसर पर विधान सभा संचालक मनीष शर्मा ने सभी सदस्यों एवं एनआईसी, रायपुर के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक पी.के.मिश्रा, सौरभ दुबे वैज्ञानिक डी, ज्योति शर्मा वैज्ञानिक सी के सहयोग हेतु भी आभार व्यक्त किया।

भगवान राम के खिलाफ टिपण्णी पर बिफरे मंत्री केदार कश्यप, कहा-

कांग्रेस का वास्तविक चेहरा सामने आया, इसलिए दे रहे ऐसा बयान

रायपुर। भगवान राम को लेकर की जा रही राजनीति पर मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूरे सिस्टम को खराब करने की कोशिश की। वास्तविक चेहरा सामने आया है, और धर्म विरोधी हो गए हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। भगवान राम पर राजनीति बर्दाश्त नहीं, यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है।

मंत्री केदार कश्यप ने मीडिया से चर्चा में कहा कि राजनीति करना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास- जैसे विषयों पर पर करें। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। दंडकारण्य हमारी आस्था का केंद्र है। पद चरण पड़े थे, इसलिए कहा जाता है कि वहां कांटा नहीं है। भगवान राम का मंदिर बना है, हम सब जाएंगे। राम सबके हैं इसमें क्या कांग्रेस-बीजेपी।

वहीं पखांजूर में हुई बीजेपी नेता असीम राय की हत्या पर केदार कश्यप ने शोक जताते हुए कहा कि यह हम सबके के लिए क्षति है। सोमवार को वहां गए थे, और मामले की पूरी जांच होगी। मामले के अलग-अलग पहलू बताए गए हैं। सभी

पहलुओं पर जांच की जाएगी। वहीं मंत्री ने हत्या के पीछे राजनीतिक षडयंत्र होने की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में लगातार मामले सामने आए हैं। जरूर राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है।

मंत्री ने कांग्रेस के नए प्रभारी का दौरा और कार्यकारिणी बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि कितने पैराशूट यहां उतारेंगे, कितने बाहर से आयेंगे तब देखेंगे। लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है। कई विषयों पर कुमारी सैलजा पर आरोप लगाए गए थे। वैसा आरोप सचिन पायलट पर ना लगे। सैलजा पर पैसा के लेनदेन के आरोप लगे थे। इस बार ऐसा ना हो कांग्रेस के लोगों पर हमारी संवेदना है।

लोकसभा की तैयारियों पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हमारी क्लस्टर की बैठक होना तय है। विधानसभा की बैठक भी होना तय है। सभी मंत्री काम कर रहे हैं। एक्शन प्लान बनाया हुआ है कि कैसे विभाग काम करेगा। विधायकों को लोकसभा टिकट देने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि बीजेपी में एक छोटा कार्यकर्ता बड़े स्तर का नेता बन सकता है।

वहीं सीट शेयरिंग और 9 राज्यों में गठबंधन पर केदार कश्यप ने कहा कि इंडी गठबंधन में आपसी तालमेल नहीं बन रही है। अपने हितों के लिए गठबंधन बनाया गया है। देश हित से उनका कोई वास्ता नहीं है।

टी राजा के स्वागत में जुटा गुढ़ियारी हनुमान मंदिर ट्रस्ट

श्रीमद् भागवत कथा के दौरान 23 को आएंगे रायपुर

रायपुर। गुढियारी के अवधपुरी मैदान में 19 से 25 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा के दौरान विशाल धर्मसभा हिन्दू हृदय सम्राट व हैदराबाद के भाग्यनगर से भाजपा विधायक टी. राजा सिंह 23 जनवरी को शामिल होंगे। उनके स्वागत की तैयारियों में अभी से गुढियारी हनुमान मंदिर ट्रस्ट व आयोजक कृष्ण (कान्हा) बाज़ारी परिवार अभी से जुट गया है। उनके स्वागत में 100 से अधिक कारों का काफिला माना विमानतल से मारुति मंगलम भवन तक आएगा।

श्रीमद् भागवत कथा समिति के युवा सदस्य चेतन पुरोहित महाराज ने बताया कि टी राजा सिंह के आने का मक़सद यह है कि हिन्दुओं में सनातन की लहर जगाना है क्योंकि वे हिन्दुओं को जागरुक करने के लिए जाने जाते है और इसी कारण उनके फॉलोवर भी बहुत अधिक है। उनके रायपुर आगमन की सूचना मिलते ही छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों से भी 23 जनवरी को गुढियारी के अवधपुरी मैदान में होने वाले धर्मसभा को सुनने के लिए आने वाले हैं। श्रीमद् भागवत कथा समिति, आयोजक कृष्ण (कान्हा) बाज़ारी एवं श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट इसकी तैयारी में अभी से जुट गया है क्योंकि उन्हें सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ आने वाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए 2 लाख वर्गफीट में डोम तैयार किया जा रहा है जहां किसी भी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि टी राजा सिंह का 23 जनवरी की दोपहर को 12 बजे स्वामी विवेकानंद टर्मिनल पर आगमन होगा जहां बाजारी परिवार की ओर से उनका स्वागत किया गया जाएगा, इसके बाद 100 से अधिक कारो का काफिला उनके साथ गुढियारी स्थित हनुमान मंदिर पहुंचेगा जहां वे में हनुमान जी महाराज की भव्य महा आरती कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इसके बाद विशाल धर्म सभा को संबोधित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने सूरजपुर के क्षेत्रवासियों को 30 विकास कार्यों की दी सौगात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अखिल भारतीय बिंझिया समाज के महासम्मेलन के अवसर पर सूरजपुर के जिलेवासियों को 27 करोड़ 72 लाख रूपए की लागत के 30 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने इन कार्यो पर लोकार्पण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े भी उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री द्वारा जिन कार्यों का लोकार्पण किया गया, उनमें लोक निर्माण विभाग अंतर्गत विकासखण्ड प्रतापपुर के ग्राम सरहरी से ग्राम सिंघरा के मध्य बाकी नदी में 4 करोड़ 81 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित पुल, विकासखण्ड़ रामानुजनगर में लोहरदगा नाला पर 4 करोड़ 54 लाख रूपए की लागत से निर्मित पुल, विकासखण्ड़ भैयाथान के कसकेला केवटाली मार्ग पर गोबरी नाला पर 4 करोड़ 61 लाख रूपए की लागत से निर्मित पुल शामिल है।

उन्होंने इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत विकासखण्ड़ रामानुजनगर के पटना बरगैयापारा से मोहनपुर पटेलपारा सड़क का 70.15 लाख रूपए की लागत से नवीनीकरण कार्य, विकासखण्ड प्रेमनगर के नमनाकला गौटियापारा से टाकरपारा सड़क का 78.39 लाख की लागत से नवीनीकरण कार्य तथा बिलासपुर धनवार रोड से जनार्धपुर खासपारा सड़क का 36.84 लाख रूपए से नवीनीकरण कार्य, उमेश्वरपुर से पार्वतीपुर खासपारा सड़क का 65.84 लाख की लागत से नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इसी प्रकार विकासखण्ड़ भैयाथान के भटगांव दतिमा मोड़ से राई पिपरपारा सड़क का 41.62 लाख रूपए की लागत से नवीनीकरण कार्य, बतरा नवापारा से बरौल खास सड़क का 51.27 लाख रूपए की लागत से नवीनीकरण कार्य, बरौल से जूनाधरतीपारा सड़क का 47.67 लाख रूपए की लागत से नवीनीकरण कार्य सहित कुल 3 करोड़ 91 लाख रूपए की लागत के 07 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया।

मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत विकासखण्ड़ सूरजपुर के जमदेई में 74.29 लाख रूपए की लागत की जल प्रदाय योजना, रतनपुर में 49.99 लाख रूपए की लागत की जल प्रदाय योजना, कुरूवां में 1 करोड़ 28 लाख रूपए की लागत

की जल प्रदाय योजना, सलका में 1 करोड़ 33 लाख रूपए की लागत की जल प्रदाय योजना, हर्राटिकरा में 49.97 लाख रूपए की लागत की जल प्रदाय, जयनगर में 1 करोड़ 92 लाख रूपए की लागत की जल प्रदाय योजना, कुंजनगर में 1 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत की जल प्रदाय योजना का लोकार्पण किया।

इसी तरह कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत विकासखण्ड़ सूरजपुर के कंदरई में पैन नाला के पास पुलिया निर्माण कार्य लागत 14.61 लाख रूपए, ग्राम करतमा के महादेव टिकरा में स्टॉप डेम निर्माण लागत 20.00 लाख रूपए, कोरिया के सत्तीड़ाड नदी किनारे तटबंध निर्माण कार्य लागत 19.95 लाख रूपए, कुरूवा के बाजारडाड़ में सामुदायिक हाट बाजार लागत 14.93 लाख रूपए, पतरापारा के झोझवा नाला में स्टॉप डेम निर्माण कार्य लागत 19.98 लाख रूपए, विकासखण्ड़ भैयाथान सिरसी के सरनापारा में आंगनबाडी भवन निर्माण कार्य लागत 6.50 लाख रूपए, सिरसी खास में आंगनबाडी भवन निर्माण लागत 6.50 लाख रूपए, विकास खण्ड़ प्रतापपुर सोनगरा के कुकुर डुबा नाला में स्टॉप डेम निर्माण कार्य लागत 19.89 लाख रूपए, सेमराकला के ठाडपाथर मार्ग में स्टॉप डेम निर्माण कार्य लागत 19.57 लाख रूपए, पलढा के आमानाला में स्टॉप डेम निर्माण कार्य लागत 19.94 लाख रूपए, विकास खण्ड़ रामानुजनगर पवनपुर के जमतीडबरा खाडी नाला में चेक डेम लागत 14.26 लाख रूपए, जगतपुर के खरौक झरिया नाला में चेक डेम निर्माण कार्य लागत 12.88 लाख रूपए, मदनेश्वरपुर के बाजार शेड का निर्माण कार्य लागत 14.77 लाख रूपए, का लोकार्पण किया गया।

राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष पद पर यथावत रहेंगे इदरीश गांधी

रायपुर। राज्य उर्दू अकादमी अध्यक्ष के पद पर इदरीश गांधी यथावत बने रहेंगे, हाईकोर्ट के न्यायामूर्ति जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी ने सोमवार को इसका फैसला सुनाया। नियमों का हावला देते हुए कहा कि 3 साल के कार्यकाल के पहले नहीं हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय हैं कि सामान्य प्रसाशन विभाग की ओर से 15 दिसंबर 2023 को आदेश जारी कर सकती है।

कार्यालय, सेनानी, सी.टी. जे. डब्ल्यू.. कॉलेज कांकेर (छ.ग.)

क्रमांक-सीटीजेडब्ल्यू/कांकेर/सा.अ./ज्ञापन क्र-04/23 दिनांक 08/01/2024

निविदा आमंत्रण सूचना

सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज कांकेर की ओर से तड़िक चालाक निर्माण कार्य हेतु दो लिफाफा पद्धति में ई पंजीयन के अंतर्गत द श्रेणी अथवा उससे अधिक के निविदाकारों से निविदा आमंत्रित किया जाता है।

स.क्र.	कार्य का नाम	बजट आबंटन राशि	अमानत राशि
1	तड़िक चालाक निर्माण कार्य-06 सेट	6,00,000.00	18000.00

निविदा नि:शर्त अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में रखी हुई शील बंद पेटी में प्रकाशित दिनांक 23.01.24 के दोपहर 12 बजे तक प्राप्त कि जावेगी एवं प्राप्त निविदाओं को दिनांक 24.01.2024 के दोपहर 12 बजे उपस्थित निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधी के समक्ष खोला जावेगा।

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु प्रति निविदा रु. 75/- की राशि का चालान सेनानी सीटीजेडब्ल्यू कालेज कांकेर छ.ग. के नाम से लेखाशिर्ष- 800 अन्य रिसीप्ट के नाम से स्वीकार होगा। उपरोक्त कार्य पूर्ण करने की अवधि 30 दिन तक है। निविदा प्रपत्र तथा शेष अन्य जानकारी/शर्त कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

सेनानी
सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज
कॉकेर (छ.ग.)

जी-06981/2

भारत में भ्रष्टाचारियों के लिए कामधेनु रही है राजनीति

डॉ. आशीष वशिष्ठ

हाल के दिनों में तमाम ऐसी खबरें आई जब जांच एजेंसियों ने नेताओं के यहां छापेमारी कर करोड़ो की काली कमाई पकड़ी। बीते साल दिसंबर में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को झारखण्ड के कारोबारी एवं राज्यसभा सांसद के यहां आयकर छापे में अरबों रुपये बरामद हुए। सोशल मीडिया पर सांसद की अकूत कमाई और नोटों के बंडल की तस्वीरें खूब वायरल हुईं। समाचार आये कि नोट गिनने वाली मशीनें नोट गिनते-गिनते थककर खराब हो गई। थैलों में नोट नहीं आए तो बोरों में भरा गया। कांग्रेस के जरिये सांसद बनने वाले धीरज साहू ने 2018 में राज्यसभा का सदस्य बनने के हलफनामे में अपनी संपत्ति 34 करोड़ के करीब बतायी थी। तो आखिर कैसे महज पांच साल में संपत्ति तीन सौ करोड़ पार कर गई? बहरहाल, यह घटना बताती है कि कैसे देश की राजनीति नेताओं की कमाई के लिये कामधेनु बन गई है।

राज्यसभा सांसद ने दो बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और हार गया था। फिर राज्यसभा के जरिये संसद पहुंचने की तिकड़में कीं। जाहिर है, धनबल भी उसका एक जरिया रहा होगा। ऐसा भी नहीं है कि भारी मात्रा में नकदी बरामदगी की यह पहली घटना हो। बीते दिनों ही ईडी ने हरियाणाा में अवैध खनन और अन्य मामलों में करोड़ों की नगदी बरामद की। जिन नेताओं के यहां छापेमारी हुए उनमें इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस और भाजपा के नेता व उनके करीबी शामिल हैं।

ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कोई कैसे इतनी अकूत संपत्ति जुटा लेता है। आर्थिक अपराधों पर नजर रखने वाली एजेंसियां क्यों तब खामोश थीं जब संसाधनों की लूट-खसोट जारी थी। सवाल यह भी कि कहीं ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा चुनाव प्रक्रिया के आसपास राजनीतिक लाभ के लिये तो नहीं होता? सवाल यह भी है कि क्या सत्ता पक्ष अपने राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करता है? भ्रष्टाचार उतना ही पुराना है जितनी राजनीति। फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि पहले दाल में नमक होता था और अब नमक में दाल। एक फर्क यह भी कि सामाजिक न्याय की राजनीति में उभार आने के बाद भ्रष्टाचार फूहड़ और बेशर्म भी हुआ। पुराने लोग बताते हैं कि पहली लोकसभा के समय जब फिरोज गांधी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मूंदड़ा केस उठाया तो जवाहर लाल की सरकार हिल गई थी। हिन्दुस्तान का मानस भी भ्रष्टाचार के नाम पर खूब उद्वेलित होता है। खुद कितना ही भ्रष्ट हो पर अपने नेता को ईमानदार देखना इसकी चाहत रहती है।

1977 और 1989 में क्रमशः जेपी आंदोलन और फिर राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की बोफोर्सी दहाड़ के बल पर दिल्ली का निजाम इसीलिए पलटा खा गया कि मूल में भ्रष्टाचार था। पर इधर सामाजिक न्याय की राजनीति के उभार के बाद राजनेताओं का भ्रष्टाचार और ज्यादा फला-फूला। लालू यादव और शिबू सोरेन की सरकारें रहीं हो या फिर मुलायम और मायावती की या फिर हरियाणा में ओमप्रकाश चौटाला की। कोई सरकार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से बची नहीं।

राजनीतिक इतिहास के पन्ने पलटें तो देश की आजादी के तुरंत बाद यानी 1948 में जीप घोटाला हुआ। जिन मेनन पर घोटाले के आरोप लगे थे उन्हें बाद में जवाहर लाल नेहरू ने अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया। जीप घोटाले के बाद 1951 में साइकिल आयात घोटाला सामने आया। इसके बाद 1956 में बीएचयू फंड घोटाला, 1958 में हरिदास मूंदड़ा मामला, 1960 में तेजा लोन स्कैम, 1963 में प्रताप सिंह कैरों स्कैम, 1965 में पटनायक कलिंग ट्यूब्स मामला, 1974 में मारुति घोटाला, 1976 में कुओ ऑयल डील, 1981 में अंतुले ट्रस्ट, 1987 में एचडीडब्ल्यू दलाली मामला सामने आया। ये वो मामले थे, जिनका खुलासा देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले हुआ। इसके बाद हुआ बोफोर्स घोटाला। इसकी गूंज आज भी संसद से लेकर सड़क तक सुनाई देती है। इसमें देश की कई बड़ी दिग्गज हस्तियों का नाम आया था।

2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। भव्य स्तर पर इसका आयोजन हुआ था। पूरी दुनिया से खिलाड़ी आए थे। आयोजन के एक साल बाद यानी 2011 में इस पर बड़ा दाग लगा। आरोप लगा कि इसमें करीब 70 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। इस मामले में मुख्य तौर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और उनके सहयोगियों के नाम शामिल रहे। ये बात 2010 की है। देश में इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। कहा जाता है कि इस पूरे मामले में देश के खजाने को 176 हजार करोड़ की हानि हुई। इस मामले के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व संचार मंत्री ए. राजा को जिम्मेदार ठहराया गया। दिसंबर 2017 में सीबीआई कोर्ट ने इस मुकदमे के सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। राजनेता ही नहीं, कई नौकरशाहों के यहां से भारी मात्रा में नकदी व अचल संपत्ति के कागज बरामद होने की भी खबरें सुनी जाती रही हैं। ये घटनाएं बताती हैं कि जिन राजनेताओं व नौकरशाहों पर सामाजिक न्याय व गरीबों के कल्याण की जवाबदेही थी, वे कदाचार का सहारा लेकर अपना घर भरने में लग जाते हैं। इन घटनाक्रमों से यह समझना भी कठिन नहीं है कि कैसे हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाने के कुछ समय बाद ही करोड़ों में खेलने लगते हैं। इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि हमारे लोकतंत्र में धनबल व भ्रष्टाचार कितने गहरे तक अपनी पैठ बना चुका है।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में सत्तारुढ़ डीएमके के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। इनमें से कई जेल में हैं। दिल्ली का शराब घोटाला वर्तमान में सबसे चर्चित है। आप के दो बड़े नेता तिहाड़ की रोटियां खा रहे हैं। इसी मामले में जांच एजेंसी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बार-बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन वो ईडी के सामने पेश होने की बजाय राजनीतिक ड्रामेबाजी और प्रपंचों में मगन हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी सात समन भेज चुकी है। सोरेन भी ईडी के सामने पेश होने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। बीते दिसंबर में अदालत ने उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे राकेश धर त्रिपाठी को भ्रष्टाचार के मामले में तीन साल की सजा सुनाई। बीते 22 दिसंबर को मद्रास हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीएमके नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद और 50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के गठन के बाद से भ्रष्टाचार खासकर राजनीतिक भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की गई। इससे पूर्व राजनीतिक भ्रष्टाचार पर सभी दलों की आपसी समझ और सहमति दिखाई देती थी। चुनावी मंच पर एक दूसरे को भ्रष्ट बताने की होड़ तो लगती थी, लेकिन चुनाव बाद भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मोदी ने राजनीतिक दलों की इस समझ और मूक सहमति को तोड़ा है। इसलिए जब जांच एजेंसियां किसी विपक्षी दल के नेता के यहां छापेमारी करती हैं तो एजेंसियों के दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध जैसी बयानबाजी सुनाई देती है।

जदयू ने राजद को मझधार में छोड़ा

आदित्य आनंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ देशभर के दलों को एकजुट करने वाली पार्टी जनता दल (यूनाईटेड) एक मामले में यूनाईटेड है। उसने साफ किया है कि वह जीती हुई 16 सीटों पर समझौता नहीं करेगा। उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर प्रत्याशी दिए थे। जदयू की लाइन देखिए- 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जदयू को 16-17 सीटें चाहिए। इसके बाद 40 में से 23-24 सीटें बचती हैं, जिनका बंटवारा राजद को अपने सहयोगियों के बीच करना है। मतलब, जदयू के अलावा बिहार की महागठबंधन सरकार में जो भी बंटवारा होगा, वह राष्ट्रीय जनता दल करे। यह राजद के लिए एक तरह से मझधार की स्थिति है। राज्य विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी राजद, सत्ता में शामिल सबसे छोटी पार्टी जदयू की बात मानती है तो उसे कांग्रेस-वामदलों से सिरफुटौव्वल भी करना पड़ेगा और विकासशील इंसान पार्टी समेत साथ जुड़ने वाले संभावित दलों से हाथ भी खींचना पड़ेगा। यह सब नहीं किया तो जदयू से मिली चोट का भी खुद इलाज करना पड़ेगा। विपक्षी दलों के इंडिया के फॉर्मूले से बिहार में सीट शेयरिंग का फंसना तय था और वही हुआ। इंडी एलायंस में देश की सबसे पुरानी पार्टी सबसे ज्यादा ताकतवर दिख रही है और उसी हिसाब से वह प्रतिनिधित्व चाहती है। कांग्रेस ने 10-11 सीटों की मांग रखी है। कांग्रेस ने 2019 में एक सीट पर जीत दर्ज की थी। भाजपा-जदयू के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के गठबंधन ने बाकी 39 सीटें अपने नाम की थीं। लोजपा तो भाजपा के साथ सीटों पर बात करेगी, लेकिन इस बार जदयू को फिलहाल राजद के साथ बात करनी है। और, यह बात चल भी रही है। राजद राज्य विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और सरकार में भी। जदयू राज्य विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन लोकसभा की जीती सीटों के हिसाब से भाजपा के बाद दूसरे नंबर की पार्टी। इसलिए, यह पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस और राजद की परेशानी से वामदलों में भी चिंता है और आगामी चुनाव से ठीक पहले इधर या उधर का खेमा पकड़ने वाले छोटे दल-समूह भी असमंजस में हैं। जदयू के नेताओं बाहरी तौर पर 17 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन वह अंतिम तौर पर 16 सीटों के लिए मान जाएगा। शेष रही 24 सीटों में से 16 सीट पर राजद किसी भी हालत में लड़ेगा। इससे कम सीट पर लड़ने से उसकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब, आठ सीटें बचेंगी। इनमें कांग्रेस को चार से पांच मिल जाए और वामदल को तीन से चार सीटों में बंटवारा करना पड़े तो अजूबा नहीं होगा। जदयू ने कांग्रेस को इसके लिए सीधी सीख भी दे रखी है कि बिहार में जदयू-राजद निर्णायक हैं, आप नहीं। मतलब, कांग्रेस को समझौता कराने के लिए जदयू का भी दबाव है और राजद के पास विकल्प भी नहीं। अंतिम तौर पर अगर इस रास्ते को सभी ने नहीं माना तो लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता सिर्फ कहने के लिए बचेगी।

मोदी की हैट्रिक या विपक्ष को संजीवनी!

राजकुमार सिंह

सरकार तो हर चुनाव से बनती-बिगड़ती है, पर कुछ चुनाव देश की दशा-दिशा भी तय करते हैं। 2024 का साल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लिए ऐसा ही साल साबित होने जा रहा है। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 16 जून, 2024 तक है, पर अगली यानी 18 वीं लोकसभा के लिए चुनाव अप्रैल-मई में ही हो जाने के संकेत हैं। बीते साल हुए विधानसभा चुनावों को केंद्रीय सत्ता का सेमीफाइनल बताया गया था। उनके नतीजों को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। भाजपा ने हिंदी पट्टी के तीन बड़े राज्यों में जीत के साथ साल को अलविदा कहा, पर जिस कांग्रेस को चुका हुआ मान लिया गया था, उसने भी तीन राज्यों में जीत हासिल की। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में

उसने भाजपा से सत्ता छीनी, तो तेलंगाना का ताज उन के. चंद्रशेखर राव से छीन लिया, जो पृथक राज्य तेलंगाना के संघर्ष के नायक रहे। शीतकालीन सत्र में विपक्षी सांसदों के रिकॉर्ड संख्या में निलंबन का संकेत यही है कि केंद्रीय सत्ता की जंग में समीकरण और मुद्दे ही नहीं, तेवर भी बदले नजर आएंगे। बीते साल में ही साफ हो गया कि भाजपा को लगातार दो बार अपने दम पर बहुमत मिल जाने के बावजूद अगला लोकसभा चुनाव दो गठबंधनों के बीच होगा। तीन दर्जन से भी अधिक दलोंवाले एनडीए की भाजपा घोषित अगुवा है तो 'इंडिया' नाम से बने 28 दलों के विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व अभी तय होना है। एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ेगा, जबकि विपक्ष को पीएम फेस घोषित करने या उसके बिना ही चुनाव में जाने पर फैसला अभी लेना है। तीन महीने बाद हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक से यह संकेत अवश्य मिल गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान परस्पर आई तल्खी को दूर कर रहना एक साथ ही है। आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाने के सुझाव का समर्थन किया, उससे नेतृत्व के सवाल पर ज्यादा रार का संकेत भी नहीं मिलता। अब जबकि अगले लोकसभा चुनाव बमुश्किल तीन महीने दूर हैं, विपक्ष के पास संयोजक से लेकर सीट बंटवारा और न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। बहरहाल तीसरी बार लोकसभा चुनाव में अपने नेतृत्व में भाजपा को विजयश्री से नरेंद्र मोदी जहां इतिहास रचना चाहेंगे, वहीं विपक्ष लगातार तीसरी हार से इतिहास के गर्त में डूब जाने के खतरे से बचना चाहेगा। सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने का पंडित जवाहरलाल नेहरू का 6130 दिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तो नरेंद्र मोदी को 2029 का लोकसभा चुनाव भी लड़ना और जीतना पड़ेगा, पर 18वीं लोकसभा का चुनाव जीत कर वह इंदिरा गांधी का 5829 दिन का रिकॉर्ड तोड़ने के रास्ते पर अवश्य आगे बढ़ना चाहेंगे।

मालदीव प्रकरण से सबक ले दुनिया

नीरज कुमार दुबे

भारत हमेशा 'पड़ोस प्रथम नीति' को आगे रखकर चलता है लेकिन यदि पड़ोसी ही आंख दिखाने लगे तो उसे लगे हाथ तगड़ा जवाब भी दे दिया जाता है। कर्ज में डूब चुके मालदीव को भारत ने लगातार आर्थिक मदद देकर उबारा, वहां बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अपना पैसा लगाया, भुखमरी और महामारी के समय वहां भोजन और वैक्सीन पहुँचाई। वहां के पर्यटन क्षेत्र को खड़ा करने के लिए भारतीयों ने ऐसा योगदान दिया कि माले के सरकारी खजाने में डॉलरों का ढेर लग गया। लेकिन अब वहां जो चीन समर्थक नई सरकार आई है वह लगातार भारत को अपमानित करने का काम कर रही है। भारत ने पहले तो बेहद संयमित रुख अपनाया लेकिन जब मालदीव के तीन मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां कर दीं और भारतीय पर्यटन क्षेत्र का मजाक उड़ाया तो पूरे देश ने एक साथ खड़े होकर मालदीव को ऐसा सबक सिखाया कि वह नजीर बन गया।

प्रधानमंत्री के खिलाफ मालदीव के तीन मंत्रियों की टिप्पणियों से गुस्साये भारतीयों ने मालीदव की यात्रा रद्द करनी शुरू कर दी। होटलों और हवाई टिकटों की बुकिंग रद्द होने लगी और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालीदव ट्रेंड होने लगा तो माले सरकार घबरा गयी और आनन-फानन में उन तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था। साथ ही मालदीव सरकार ने एक बयान जारी कर यह भी कहा कि मंत्रियों के बयान मालदीव की नीति के अनुरूप नहीं हैं। यही नहीं, मालदीव की पूर्व सरकार के मंत्रियों और पूर्व राष्ट्रपतियों ने भी अपने ही देश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और भरोसेमंद पड़ोसी भारत के खिलाफ की गयी टिप्पणियों को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान बताया।

जो लोग नया भारत क्या है, यह बात आज तक नहीं समझे हैं उन्हें जरा उन टिप्पणियों पर गौर फरमा लेना चाहिए जो बॉयकॉट मालीदव या पहले भारत के द्वीपों की सैर करो जैसे हैशटैग के साथ लिखी गयी हैं। जिस तरह

फिल्म उद्योग, खेल जगत और अन्य क्षेत्रों की हस्तियों ने प्रधानमंत्री के समर्थन में टिप्पणियां करते हुए मालदीव को खरी खरी सुनाई है उससे माले के पूरे पर्यटन उद्योग को दिन में तारे दिख गये हैं। भारतीयों के रुख को देखते हुए अन्य देशों ने भी बड़ी प्रेरणा ली होगी क्योंकि आज के समय में भारतीय नागरिक ही कई देशों की पर्यटन अर्थव्यवस्था में जान फूंक रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण से लक्षद्वीप के पर्यटन को भी नये पंख लगना तय हो गया है क्योंकि अधिकतर लोगों ने वहां की यात्रा की इच्छा जताई है। आने वाले दिनों में संभव है कि वहां के लिए अधिक से अधिक फ्लाइटें शुरू हो जाएं ताकि लोग आसानी से वहां पहुँच सकें।

जहां तक मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणियों पर भारत के आधिकारिक रुख की बात है तो भारतीय उच्चायोग के स्तर पर तत्काल ही आपत्ति जता दी गयी थी लेकिन अब भारत में मालदीव के राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब कर भी अच्छी तरह से सुना दिया गया है और मालदीव के कई मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई टिप्पणियों पर कड़ी चिंता व्यक्त की गई। हालांकि मालदीव सरकार अपने बचाव में तर्क दे रही है कि मोदी के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर रविवार को ही तीन उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि तीनों उप मंत्रियों ने लक्षद्वीप की यात्रा के बाद 'एक्स' पर प्रधानमंत्री की ओर से की गयी पोस्ट के लिए उनकी आलोचना की थी और कहा था कि यह केंद्र शासित प्रदेश को मालदीव के वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने का एक प्रयास है। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, युवा मंत्रालय में उप मंत्रियों- मालशा शरीफ, मरियम शिउना और अब्दुल्ला महजूम माजिद को उनके पदों से निलंबित कर दिया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह विवाद ऐसे दिन शुरू हुआ, जब मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू एक सप्ताह की चीन यात्रा पर रवाना हुए। देखा जाये तो मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है और माले की पिछली सरकार में दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्रों सहित समग्र द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति देखी गई थी। नये राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को चीन का करीबी माना जाता है। पदभार संभालने के तुरंत बाद मुइज्जू ने मालदीव से भारतीय सैन्यकर्मियों की वापसी का आह्वान किया था। माना जा रहा है कि चीन समर्थक और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के करीबी सहयोगी माने जाने वाले मुइज्जू ने चीन की उम्मीदें बढ़ा दी हैं कि भारत के दक्षिणी तट के करीब हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित द्वीपीय देश उसके समर्थन में अब नीतियों को आगे बढ़ाएगा।

बहरहाल, जहां तक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की चीन यात्रा की बात है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि इस दौरान शी जिनपिंग तथा मुइज्जू दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने पिछले सप्ताह कहा था कि राष्ट्रपति शी आठ से बारह जनवरी तक राजकीय यात्रा पर आ रहे मुइज्जू के स्वागत में भोज देंगे। दोनों राष्ट्राध्यक्ष बातचीत करेंगे और 'सहयोग दस्तावेजों के हस्ताक्षर समारोह' में भाग लेंगे। यहां यह भी ध्यान रखे जाने की जरूरत है कि मालदीव के राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने 'पहले भारत' की नीति का पालन किया था और भारत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए थे।

आखिर नीतीश कुमार को लेकर क्यों मचा है इतना कोहराम

शशिधर पाठक

देश में भजपा और एनडीए को 2019 में जीती 39 सीटों की तुलना में 2024 में सबसे बड़ा झटका बिहार से लगने की संभावना है। भाजपा इस झटके की संभावना से उबरना चाहती है, जबकि 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी से एक बार फिर बिहार की राजनीति के क्षितिज पर छा जाना चाहते हैं। बिहार से जुड़े कई नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार की इसी महात्वाकांक्षा को लेकर सबसे बड़ा कोहराम मचा है, जबकि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई देती। शांत, संयत और अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।

लगभग सभी का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा फायदा राजद को होगा। उसकी लोकसभा में कोई सीट नहीं है। सब मिलकर लड़ेंगे तो लोकसभा में सीटें होंगी। जद(यू) की 2019 की 16 सीटें फिर से आएंगी या नहीं, कहना मुश्किल है। एनडीए की भी घटेंगी। इसे लेकर सब असमंजस में हैं।

राजेश ठाकुर राजनीति शास्त्र से पीएचडी हैं। उनका ध्यान बिहार की राजनीति पर है। एक बड़े राजनेता के लिए काम कर रहे हैं। वह कहते हैं कि अभी जो स्थिति है, उसमें एनडीए 2024 में 39 सीटें नहीं पा सकती। जद(यू) की कितनी आएंगी, वह बाद की बात है। नीतीश का मुख्य ध्यान राज्य की नंबर वन पार्टी बनने और अपनी गिरती छवि को निखारने पर है। 2010 में जद(यू) राज्य की सबसे बड़ी पार्टी (22.58 प्रतिशत वोट,115 सीट) थी। 2020 के विधानसभा में 15.39 प्रतिशत वोट के साथ तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। 75 सीट और 23.11 प्रतिशत वोट के साथ राजद सबसे बड़ी, जबकि 19.46 और 74 प्रतिशत वोट के साथ भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी।

राजेश कहते हैं कि 2024 के प्रस्तावित लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक फायदा राजद को होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी। इस बार यह संख्या मिल पाना मुश्किल है। सबसे अधिक नुकसान एनडीए को होने की उम्मीद है। राजेश की सामाजिक आधार पर गणना के मुताबिक यदि नीतीश इंडिया गठबंधन और खासकर महागठबंधन से छिटक जाएं तो भाजपा को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। वह कहते हैं कि जितना नीतीश की छवि और उनकी पार्टी कमजोर होगी, उसका एक अनुपात में लाभ भाजपा और आरजेडी दोनों को होगा। इस स्थिति से नीतीश कुमार वाकिफ हैं। राजेश ठाकुर कहते हैं कि नीतीश का सूचना तंत्र काफी तेज है। वह हवा भांपने में भी माहिर हैं। यही कारण है कि बिना पूर्ण बहुमत पाए वह दूसरे दलों के सहारे करीब दो दशक से सत्ता में हैं। नीतीश को यह भी पता है कि वह जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरेंगे, उस दिन के बाद से उनकी साख तेजी से गिरेगी। उनकी पार्टी भी टूट का शिकार होगी। इसलिए वह इसको लेकर काफी संजीदा हैं। इसलिए नीतीश के लिए केन्द्रीय सत्ता में भागीदारी की तुलना में बिहार में अपना और पार्टी का वर्चस्व अधिक महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने का अवसर भर चाहिए। गिरिराज सिंह भविष्यवाणी कर चुके हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ दिन के ही मेहमान हैं। नीरज कुमार जद(यू) के बड़े नेता हैं। साफ कहते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश हो रही है। नीरज कुमार सवाल पूछते हैं कि आखिर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रश्न कहां से आया? हमने तो कोई ऐसा आवेदन नहीं किया था?

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक इसलिए बनाने की साजिश रची जा रही है ताकि वह प्रधानमंत्री का चेहरा न बन पाएं? नीतीश की ही पार्टी के नेता और मंत्री मदन साहनी भी नीतीश को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने की मांग कर रहे हैं। जद(यू) में नीतीश का कोई और खास है तो वह बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी हैं। चौधरी के मुताबिक सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। नाराजगी के मुख्य कारण में वह इसी का संकेत कर रहे हैं।

चुनाव रणनीतिकार से नेता बनने की जद्दोजहद कर रहे प्रशांत किशोर भी यह कहने से बाज नहीं आते कि इंडिया गठबंधन में कोई नीतीश को भाव नहीं दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इंडिया गठबंधन में संयोजक पद पर नीतीश कुमार से जुड़े सवाल को लेकर कहा कि यह कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। खरगे ने कहा कि अगले 10-15 दिन में इंडिया गठबंधन में सभी पदों पर नियुक्तियां कर ली जाएंगी। खरगे के बयान से अभी कहीं नहीं लग रहा है कि गठबंधन में किसी तरह का कोई खतरा है।

ललन सिंह ने अभी जद(यू) नहीं छोड़ी है। जद(यू) के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए हैं। इसी सप्ताह नीतीश और ललन सिंह का तालमेल तब देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री उन्हें (ललन) को बुधवार को उनके घर छोड़ने गए। जद(यू) के सूत्र कहते हैं कि दोनों में हर रोज बात होती है, लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार को लेकर मीडिया में बहुत कुछ आया। यहां तक कि ललन सिंह 12 विधायकों के साथ जद(यू) तोड़ने की तैयारी कर रहे थे?

दो बातें सही हैं। पहली यह कि ललन सिंह भाजपा के जद(यू) में मुखर आलोचक हैं। उनके कारण उपेन्द्र कुशवाहा ने नीतीश का साथ छोड़ा। आरसीपी भी अलग हुए। दूसरा ललन सिंह, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में एक अलग केमिस्ट्री है। कुछ ऐसी ही केमिस्ट्री भाजपा के सुशील मोदी के साथ भी है। इस केमिस्ट्री को लेकर अफवाह और सच में फासला कभी कभी इतना कम हो जाता है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसकी भाजपा में एक सजा सुशील मोदी भी भुगत रहे हैं। वह नीतीश कुमार पर सबसे तीखा हमला बोल देते हैं, लेकिन उन्हें नीतीश कुमार से संपर्क रखने वाला भी माना जाता है।

दूसरी तरफ बिहार भाजपा बयान देने में माहिर कुछ नेता उस समय चुप्पी साधने में भरोसा करते हैं, जब नीतीश कुमार के एनडीए में फिर से शामिल होने की खबरें चलने लगती हैं। 2022 में राजद के साथ जाने के बाद इस तरह की खबरें कई बार उड़ चुकी हैं। हर बार इस तरह का ट्रेंड दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही इस तरह की अफवाह ठंडी होती है, फिर बिहार सरकार और नीतीश कुमार को लेकर बयान तेज हो जाते हैं।

वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा के मुताबिक दरसल यहां भाजपा का मकसद एक भ्रम को बनाए रखना होता है। ताकि नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि कमजोर होती रहे। संजय के मुताबिक, भाजपा के रणनीतिकारों को पता है कि जब नीतीश कुमार को अपनी और पार्टी की छवि पर असर पड़ता दिखाई देता है तो वह परेशान होते हैं। राजद के कुछ नेता के व्यवहार इसमें आग में घी का काम कर देते हैं। दरअसल, नीतीश कुमार को एक कला आती है। शरद पवार के वाक्य का इस्तेमाल किया जाए तो वह राजनीति की रोटी नहीं जलने देते। समय पर पलट लेते हैं। कीर्ति आजाद के साथ काम कर चुके सूत्र का कहना है कि 2020 में नीतीश मात खा गए थे। अमित शाह ने बहुत बारीक राजनीति की। नीतीश कुमार की पार्टी विधान सभा में 43 सीट पर आ गई। इसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन 43 सीट का दर्द अभी भी नहीं भूल पा रहे हैं। उन्हें यही संख्या ठीक करनी है।

क्या है प्रधानमंत्री मोदी का लक्षद्वीप एजेंडा?

अजय सेतिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को लक्षद्वीप गए थे।उन्होंने वहां सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कई परियोजनाओं के वायदे किए। उनके कार्यक्रमों का कई टीवी चैनलों ने सीधा प्रसारण किया।लोग हैरान थे कि क्या मोदी 95 प्रतिशत मुस्लिम आबादी और सिर्फ 55 हजार वोटरों वाली लक्षद्वीप लोकसभा सीट का लक्ष्य साध कर लक्षद्वीप गए थे। अगले दिन दोपहर बाद नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किये।इन तस्वीरों की पहले दिन किसी को भनक तक नहीं थी।तस्वीरें लोड होते ही सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगा।सिर्फ भारत नहीं, लक्षद्वीप दुनिया भर में ट्रेंड करने लगा। तस्वीरों और वीडियो की शूटिंग समुद्र किनारे की गई थी। यह वैसे ही एक विज्ञापन जैसी वीडियो है, जैसी वीडियो उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कच्छ की बनवाई थी।फर्क सिर्फ यह था कि वीडियो में अमिताभ बच्चन की जगह नरेंद्र मोदी मॉडल थे।आप को वह डायलॉग जरुर याद आया होगा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। अमिताभ बच्चन गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे।तो नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिखाई दिए।और वह सच में कहते दिखाई दे रहे हैं कि कुछ दिन तो गुजारो लक्षद्वीप में।बाकी सब तो प्रधानमंत्री के नाते मोदी के प्रोग्राम थे, वह असल में मॉडलिंग करने ही लक्षद्वीप गए थे। अगर मोदी की जगह अमिताभ बच्चन या कोई अन्य हीरो या हीरोईन मॉडल होती, तो यह विज्ञापन भारत तक ही सीमित हो कर रह जाता।मोदी का लक्ष्य पूरा नहीं होता।इस मॉडलिंग के पीछे छिपा है एक बड़ा लक्ष्य, जिसे राजनीतिक दिमाग वाले लोग सोच भी नहीं सकते।बल्कि एक नहीं, दो दो लक्ष्य हैं।पहला लक्ष्य मालदीव के मुकाबले का टूरिस्ट स्पॉट लक्षद्वीप को बताना है, और दूसरा लक्ष्य चीन की तरफ से बढ़ते खतरे को रोकना है। 2013 में भारत ने दो हेलीकाप्टर और 2020 में एक सैन्य विमान मालदीव को उपहार में दिए थे।हेलीकाप्टरों और विमानों का इस्तेमाल मालदीव के अलग अलग द्वीपों के बीमारों और घायलों को एयर लिफ्ट करने के लिए किया जाता था।विमान और हेलीकाप्टरों का संचालन करने के लिए 75 भारतीय सैनिक भी मालदीव में तैनात थे।इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना को मालदीव के जलक्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की इजाजत मिली थी।सामरिक दृष्टि से यह समझौता भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था। 2022 में राष्ट्रपति पद के चीन समर्थक उम्मीदवार मोहम्मद मोइज्जू ने अपने चुनाव अभियान के दौरान भारत के खिलाफ जम कर प्रचार किया।उन्होंने कहा अगर वह जीत गए, तो भारतीय सैनिकों को वापस भारत भेजा जाएगा।वह चुनाव जीत गए, और राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही उन्होंने भारत से अपने 75 सैनिक वापस बुलाने की मांग की।जिसके लिए भारत को तैयार होना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के साथ हुआ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का समझौता भी रद्द कर दिया।ऐसा लगता है कि मालदीव अब यह समझौता चीन के साथ करना चाहता है।चीन अगर मालदीव को अपना नया अड्डा बना लेता है, तो भारत के लिए खतरे की घंटी होगा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले खतरे को तभी भांप लिया था, जब चीन समर्थक मोहम्मद मोईज्जू मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए थे। मालदीव के समुद्री तट अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं।वहां समुद्र के नीचे बने होटल, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं।पर्यटन ही मालदीव की कमाई का प्रमुख स्रोत है।करीब डेढ़ लाख भारतीय हर साल मालदीव जाते हैं। मालदीव 36 टापूओं वाले भारत के केंद्र शासित लक्षद्वीप से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है।लक्षद्वीप के समुद्री तट भी मालदीव जितने ही खूबसूरत हैं, लेकिन पर्यटन की कोई सुविधा नहीं थी।

लोकसभा में उतरेंगे राज्यसभा में रहे मंत्री

समीर चौगांवकर

लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अपनाए गए मॉडल को लागू करेगी। जिस तरह विधानसभा चुनाव में लोकसभा सांसदों को मैदान में उतार दिया था, उसी तर्ज पर कई बड़े नेताओं और मंत्रियों को जो राज्यसभा से सांसद हैं, उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने यह प्रयोग समिति स्तर पर किया था। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि मोदी की लोकप्रियता अपने चरम पर है और संगठन भी जमीनी स्तर पर मजबूत है, ऐसे में मोदी सरकार के मंत्री जो राज्यसभा से हैं, उनको लोकसभा चुनाव में उतार कर जीत हासिल की जा सकती है। मोदी और शाह भी चाहते हैं कि केन्द्रीय मंत्रियों की पहचान अब बन चुकी है, ऐसे में उनको लोकसभा चुनाव लड़ने का साहस करना चाहिए इससे उनकी खाली सीटों पर किसी अन्य को राज्यसभा भेजा जा सकेगा।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद राज्यसभा से हैं। ऐसे में उनके सामने भी चुनाव लड़ने की चुनौती होगी। हालांकि खुद जेपी नड्डा इस बात से इंकार कर रहे हैं लेकिन समझा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी नड्डा से हिमाचल की किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कह सकते हैं। अगर भाजपा के अध्यक्ष लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के अन्य राज्यसभा सांसदों को भी चुनाव लड़ने का नैतिक आधार बनेगा। फिलहाल मोदी सरकार में 18 मंत्री राज्यसभा से हैं। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और राज्यसभा सांसद धर्मेन्द्र प्रधान ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। धर्मेन्द्र प्रधान 2004 में उड़ीसा की देवगढ़ सीट से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। इस सीट का परिसीमन होने के बाद इसे दो सीटों ढ़ेकानाल और संबलपुर में बांट दिया गया। इन दोनों सीटों में से किसी एक सीट से धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते है।

मोदी और शाह के गृह राज्य गुजरात से भी मोदी के दो केन्द्रीय मंत्रियों के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। केन्द्रीय स्वास्थ्य और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया को सौराष्ट्र से आने वाली राजकोट से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। सौराष्ट्र के अलावा मनसुख भाई मंडाविया के गृह क्षेत्र की सीट भावनगर से भी उम्मीदवार बनाने की चर्चा है। केन्द्रीय पशुपालन मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला को गुजरात की अमरेली से भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। राजस्थान से भी राज्यसभा से आने वाले दो केन्द्रीय मंत्रियों को भाजपा चुनाव मैदान में उतार सकती है। केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ओडिसा कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं और राज्यसभा में भी उड़ीसा से ही हैं, लेकिन उनका गृह राज्य राजस्थान है। अश्विनी वैष्णव जयपुर से लोकसभा लड़ सकते हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि भाजपा हाईकमान अश्विनी वैष्णव को उड़ीसा की ही किसी सीट से मैदान में उतार दे।

राजस्थान से राज्यसभा सांसद और केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव को भी राजस्थान की अलवर सीट से लड़ाया जा सकता है। अलवर सीट से सांसद बाबा बालकनाथ विधायक बन चुके है। ऐसे में भूपेन्द्र यादव के अलवर सीट से लड़ने की प्रबल संभावना है। भूपेन्द्र यादव दिल्ली से सटी सीट गुरूग्राम से भी लड़ सकते हैं। मोदी कैबिनेट में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही निर्मला सीतारामन को तमिलनाडु की मदुरै सीट से उतारा जा सकता है। खबर है कि निर्मला सीतारामन को उनकी पंसदीदा सीट बताने के लिए कहा गया है। तमिलनाडु से मोदी सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी पार्टी चुनाव पार्टी लड़वा सकती है। जयशंकर के माता पिता जरूर तमिलनाडु से हैं लेकिन उनका जन्म दिल्ली में और पढ़ाई भी दिल्ली में हुई है।

उल्लेखनीय है कि 2023 में मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने पर भाजपा ने जो महाजनसंपर्क अभियान चलाया, उसमें जयशंकर को दिल्ली की चार लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे में संभावना है कि पार्टी विदेश मंत्री जयशंकर को दिल्ली की किसी सीट से मैदान में उतारे। संभावना है कि मीनाक्षी लेखी की सीट से भी जयशंकर को टिकट दिया जा सकता है। मोदी सरकार के एक और मंत्री पीयूष गोयल के भी लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। 2010 से पीयूष गोयल लगातार राज्यसभा सांसद और 2014 से लगातार मोदी सरकार में मंत्री है। पीयूष गोयल को पुणे लोकसभा सीट से उतारा जा सकता है। पिछले पांच लोकसभा चुनाव की बात करें तो तीन चुनाव में भाजपा यहां से जीत रही है। भाजपा ऐसे राज्यसभा सांसदों को भी लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है जो मंत्री नहीं है लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने को उत्सुक है। इन राज्यसभा सांसदों में भाजपा के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी उत्तराखंड से, पूर्व लोकसभा सांसद और वर्तमान में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी शामिल हैं।

2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुल 11 राज्यसभा के सांसदों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था जिनमें से सात को हार का सामना करना पड़ा। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर से, केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से, केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से जीते थे। वहीं पूर्व नौकरशाह और मोदी सरकार में राज्य मंत्री रहे हरदीप पुरी अमृतसर से हार गए थे और मोदी सरकार के एक और मंत्री केजे अल्फांस एनाकुर्लम सीट से तीसरे नंबर पर रहे थे। भाजपा को लग रहा है कि अगर उसे 2019 में मिली 303 से अधिक सीटें जीतनी है तो विपक्ष की मजबूत सीटों पर भी दमदार उम्मीदवार खड़े करने होंगे। पार्टी का आकलन है कि जिन सीटों से केन्द्रीय मंत्री लड़ते हैं उसके आसपास की सीटों पर भी उसका असर पड़ता है। भाजपा के एक राष्ट्रीय नेता का कहना है कि %जब विपक्ष हर एक सीट पर एक साझा उम्मीदवार देने की तैयारी कर रहा हो तो ऐसे में अगर भाजपा केन्द्र में मंत्री रहे राज्यसभा सांसद चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इन विपक्षी नेताओं को उनकी सीटों पर चुनौती देने के मामले में भाजपा बेहतर स्थिति मे रहेगी।%

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के भीतर एक व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया था, जिसके अंतर्गत लगातार दो बार राज्यसभा सांसद रहे नेताओं को तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजा जाए। मोदी ने कहा था कि कोई सांसद यह कहता है कि वह लगातार तीन बार से राज्यसभा का सासंद है तो इसका मतलब है कि पार्टी अन्य विकल्पों पर विचार नहीं कर रही है। मोदी का मानना है कि एक ही व्यक्ति को दो बार से अधिक राज्यसभा में भेजना यह दर्शाता है कि पार्टी की उस पर अत्याधिक निर्भरता है और वह व्यक्ति निर्भरता का पूरा लाभ ले रहा है। मोदी ने साफ कहा था कि पार्टी में ऐसी अपरिहार्य स्थिति किसी भी नेता को लेकर नहीं बननी चाहिए।

पार्टी की इसी लाईन को अमित शाह ने आगे बढ़ाते हुए राज्यसभा से सांसद और मोदी सरकार में मंत्रियों से दो टूक कह दिया है कि चुनाव लड़ने की तैयारी रखें और अपनी पंसद की सीट पार्टी नेतृत्व को अवगत करा दे। अगर आपके पास सीट का विकल्प नहीं है तो पार्टी आपके लिए उचित सीट उपलब्ध करा देगी। मोदी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में साफ कहा था कि कोई लोकसभा सीट न होना और जीतने की गारंटी न होना बार-बार राज्यसभा भेजने का आधार नहीं हो सकता है। दरअसल मोदी का मानना है कि एक नेता के रूप में आप संगठन में बड़े पद पर रहें, किसी राज्य के चुनाव प्रभारी रहते प्रदेश के नेताओं को चुनाव जीतने की रणनीति भी बताएं, केन्द्र में मंत्री भी रहें लेकिन चुनाव लड़ने से तौबा करें और राज्यसभा सांसद बन कर मंत्री पद को सुभोशित करें, यह स्वीकार्य नहीं है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

पाशुपतब्रह्मोपनिषद् (भाग-8)

गतांक से आगे...

जो साधक योगी- ब्रह्मज्ञानी होता है, वह प्राणि मात्र को ब्रह्म के रूप में देखता है। इस कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि की भावना भी उसके लिए भोज्य (ग्राह्य-पाच्य) है। मृत्यु ही जिस ब्रह्म का अन्न (भोज्य पदार्थ) है, ऐसे ब्रह्म को जानने वाला साधक भी तदनुरूप ही हो जाता है तथा यह सम्पूर्ण जगत् ही उसके लिए भोज्य (ग्राह्य) हो जाता है। जब इस विश्व की आत्मा के रूप में अनुभूति की जाती है, तो वह भोज्य रूप हो जाता है तथा आत्मा रूप से अविनाशी ब्रह्म सतत उसका भक्षण करता रहता है।

जिसका आभास हो जाने से यह विश्व भोज्य पदार्थरूप हो जाता है तथा वह जब आत्मस्वरूप ज्ञात हो जाता है, तो निश्चय ही वह ब्रह्म के द्वारा भक्षित होता है। इस तरह से ब्रह्म स्वयं ही अपने स्वरूप का भक्षण करता है, इसका कारण यह है कि उससे (ब्रह्म से) भोज्य पदार्थ अलग ही नहीं है। जो अस्तिता का रूप है, वही ब्रह्म के अस्तित्व का लक्षण रूप है। सत्ता का लक्षण ही अस्तित्व माना जाता है तथा ब्रह्म से सत्ता पृथक् नहीं होती। ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता है ही नहीं और न माया कोई वास्तविक वस्तु ही होती है। योगी साधकगण माया की कल्पना अपनी अन्तरात्मा से ही करते हैं। वह ब्रह्मज्ञान से बाधित होती हुई। उन (साधक गणों) को साक्षीरूप में प्रतिभासित होती है।

इस प्रकार से जिस ज्ञानी साधक को ब्रह्म के ज्ञान-विज्ञान की सम्पन्नता की अनुभूति हो गई है, वह चाहे इस सम्पूर्ण विश्व का अपने समक्ष दर्शन करता रहे; किन्तु वह उसे अपने से अलग कभी नहीं मानता। ऐसी ही यह उपनिषद् (रहस्यात्मक ज्ञान) है।

विश्व हिन्दी दिवस

ललित गर्ग

विश्व योग दिवस, विश्व अहिंसा दिवस आदि भारतीय अस्मिता एवं अस्तित्व से जुड़े विश्व दिवसों की श्रृंखला में विश्व हिन्दी दिवस प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिये जागरूकता पैदा करना तथा हिन्दी को अन्तरराष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी, 2006 को मनाया गया था। आज हिन्दी विश्व की सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली तीसरी भाषा है, विश्व में हिन्दी की प्रतिष्ठा एवं प्रयोग दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन देश में उसकी उपेक्षा एक बड़ा प्रश्न है। सच्चाई तो यह है कि देश में हिंदी अपने उचित सम्मान को लेकर जूझ रही है। राजनीति की दूषित एवं संकीर्ण सोच का परिणाम है कि हिन्दी को जो सम्मान मिलना चाहिए, वह स्थान एवं सम्मान आजादी के अमृत महोत्सव मना चुके राष्ट्र में अंग्रेजी को मिल रहा है। अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं की सहायता जरूर ली जाए लेकिन तकनीकी एवं कानून की पढ़ाई एवं राजकाज की भाषा के माध्यम के तौर पर अंग्रेजी को प्रतिबंधित या नियंत्रित किया जाना चाहिए। आज भी भारतीय न्यायालयों में अंग्रेजी में ही कामकाज होना राष्ट्रीयता को कमजोर कर रहा है। हिन्दी को प्रतिष्ठापित करने एवं उचित सम्मान देने की जरूरत इसलिये है कि हिन्दी के बहुआयामी एवं बहुतायत उपयोग में ही राष्ट्रीयता की मजबूती है, जीवन है, प्रगति है और शक्ति है किन्तु इसकी उपेक्षा में विनाश है, अगति है और स्खलन है।

एथनोलॉग के वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण में बताया गया है कि दुनियाभर की 20 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 6 भारतीय भाषाएं हैं, इनमें हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गयी है। वर्तमान में 637 मिलियन लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व को समेट हिंदी अब विश्व में लगातार अपना फैलाव कर रही है, हिन्दी राष्ट्रीयता की प्रतीक भाषा है, उसको राजभाषा बनाने एवं राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठापित करने के नाम पर भारत में उदासीनता एवं उपेक्षा की स्थितियां परेशान करने वाली है, विडम्बनापूर्ण है। विश्वस्तर पर प्रतिष्ठा पा रही हिंदी को देश में दबाने की नहीं, ऊपर उठाने की आवश्यकता है। हमने जिस त्वरता से हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की दिशा में पहल की, उसी त्वरा से राजनैतिक कारणों से हिन्दी की उपेक्षा भी है, यही कारण है कि आज भी देश में हिन्दी भाषा को वह स्थान प्राप्त नहीं है, जो होना चाहिए। देश-विदेश में इसे जानने-समझने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है।

हिन्दी को उसका गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी के प्रयत्नों को राष्ट्र सदा स्मरणीय रखेगा। क्योंकि मोदी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देकर न केवल हिन्दी को गौरवान्वित किया बल्कि देश के हर नागरिक का सीना चौड़ा किया। भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में विश्व हिन्दी दिवस मनाया जाने लगा क्योंकि भारत और अन्य देशों में 70 करोड़ से अधिक लोग हिन्दी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं।

दुनियाभर में हो रही बांग्लादेश के विपक्ष विहीन चुनाव की चर्चा?

संजय तिवारी

7 जनवरी को बांग्लादेश में अभी मतदान खत्म भी नहीं हुआ था कि दुनियाभर की समाचार एजंसियों ने चुनाव परिणाम बताने शुरु कर दिये थे। %बांग्लादेश में एक बार फिर अवामी लीग की सरकार बनना तय हो गया। शेख हसीना पांचवीं बार प्रधानमंत्री बनेगी। दुनियभार की समाचार एजंसियों की यह भविष्यवाणी अनायास तो नहीं थी। अगले दिन 8 जनवरी को जब चुनाव परिणाम आने लगे तो वही हुआ जो दुनियाभर के पोलिटिकल पंडित भविष्यवाणी कर रहे थे। मुजीबुर्रहमान की बेटी शेख हसीना की पार्टी को एक बार फिर दो तिहाई से अधिक बहुमत मिल गया। बांग्लादेश की जातीय संसद में 300 सीटें हैं जिसमें से 299 पर मतदान हुआ था। इस 299 सीटों में से 222 सीट अवामी लीग को मिली है। 62 निर्दलीय जीते हैं जबकि जातीय पार्टी को 11 सीटें मिली हैं।

जब सबकुछ ठीक है। चुनाव हुए। कई दलों ने चुनाव भी लड़ा। लगभग शांतिपूर्वक 40 प्रतिशत मतदान भी हुआ तो फिर दुनियाभर की समाचार एजंसियां चुनाव परिणाम आने से पहले ही परिणामों की इतना सटीक भविष्यवाणी कैसे कर रही थीं? केवल जीत की भविष्यणावी भर नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश मीडिया हाउस इसे विपक्ष विहीन एकतरफा चुनाव बताकर इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं? असल में लगातार तीसरी बार बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीऐनपी) ने आम चुनाव के बॉयकॉट का ऐलान किया था। बीएनपी 2014 से जातीय संसद के चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है। बीएनपी बांग्लादेश की बड़ी राजनीतिक हैसियत वाली पार्टी है और चार बार सरकार बना चुकी है।

इस पार्टी की स्थापना पाकिस्तान समर्थक जनरल जियाउर्रहमान ने 1978 में की थी। उनकी विधवा बेगम खालिदा जिया इस समय इस पार्टी की प्रमुख हैं जो दो बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। जियाउर्रहमान खुद भी बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके थे और 1981 में बांग्लादेश आर्मी के ही लोगों ने पाकिस्तानी समर्थक होने के कारण उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन जियाउर्रहमान की हत्या के बाद भी बीएनपी की पाकिस्तानी परस्ती में कमी नहीं आयी। अवामी लीग की शेख हसीना कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ हैं और वो एक साझा संस्कृति वाले बांग्लादेश की पक्षधर हैं। इसके उलट बीएनपी मजहबी राजनीति करती है और उसके आसपास ही बांग्लादेश के सारे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पलते बढते हैं जिनको मुख्य रूप से पाकिस्तान से समर्थन मिलता है। इसलिए 2013 में बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब कट्टरपंथी और पाकिस्तान परस्त जमात ए इस्लामी को बैन कर दिया तब शेख हसीना ने जमात ए इस्लामी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। इस्लामिक संगठनों द्वारा जब इस कार्रवाई का विरोध किया गया तब शेख हसीना ने ऐसे विरोध को भी कठोरता से कुचल दिया था।

2016 में जमात ए इस्लामी के चीफ मोतिउर्रहमान को फांसी देकर शेख हसीना ने साहसिक कदम उठाया क्योंकि मोतिउर्रहमान पर बांग्लादेश में अवैध तरीके से हथियार लाकर बांग्लादेश को अस्थिर करने का आरोप लगा था। मोतिउर्रहमान अवामी लीग की सेकुलर नीति का विरोधी था और बांग्लादेश की खुफिया एजंसियों को अंदेशा था कि पाकिस्तान की मदद से वह बांग्लादेश से शेख हसीना को खत्म करने का प्लान बना रहा था। उसके हथियारों की तैयारी भी इसी दिशा में थी। अब क्योंकि शेख हसीना कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ हैं और सबसे बड़ी बात कि भारत से बेहतर रिश्ता रखने की पक्षधर हैं, इसलिए बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक दल या संगठन आम चुनावों का बहिष्कार करने लगे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का बहिष्कार इसी कारण से है। वरना कोई कारण नहीं था कि वह इस तरह से लगातार तीसरी बार चुनावों का बहिष्कार करती। इसी बहिष्कार को लेकर दुनियाभर की समाचार एजंसियां और इस्लामिक समर्थक बांग्लादेश के चुनावों को एकतरफा चुनाव बताते आ रहे हैं।

यह बात सही है कि बीएनपी के बहिष्कार के कारण मतदान में भी कमी आती है और बांग्लादेश में चुनाव को लेकर वैसा उत्साह नहीं रहता जैसा होना चाहिए। बांग्लादेश के लोकतंत्र समर्थक ऐसी परिस्थिति से दुखी हैं। बांग्लादेश की चुनाव विश्लेषक शरमीन मुर्शिद कहती हैं- यह बिना व्याकरण वाला चुनाव था। मैंने ऐसा कोई चुनाव नहीं देखा। यह किसी भी चीज़ में फिट नहीं बैठता। परिणाम वही हैं जो होने चाहिए थे। शरमीन कहती हैं कि यह एक ऐसा चुनाव था जिसमें एक ही दल (अवामी लीग) पक्ष और विपक्ष दोनों ओर था। उसके साथ 27 छोटे दल थे और सब अवामी लीग के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ रहे थे। कई जगह तो विपक्ष का उम्मीदवार भी अवामी लीग द्वारा ही खड़ा किया गया था ताकि मतदान हो सके।

बांग्लादेश के अर्थशास्त्री अनु मोहम्मद कहते हैं कि बांग्लादेश में आम चुनाव एक लोक उत्सव की तरह होते हैं। चुनाव ही ऐसा समय होता है जब जनता अपने वोट की मालिक नजर आती है। लेकिन 2014 से अब 2023 तक वह उत्साह कहीं दिखाई नहीं देता। जो कुछ हुआ है वह महज एक औपचारिकता थी, जिसे पूरा कर लिया गया है। अनु मोहम्मद आगे कहते हैं कि जो लोग इन चुनावों (2014 से 2023) के दौरान मतदाता बने उन्हें उस उत्सवी माहौल का अनुभव नहीं हुआ जो होना चाहिए था। पूरे चुनाव के दौरान देशभर में कर्फ्यू जैसे हालात बने रहे। अवामी लीग के समर्थक जरूर सक्रिय दिखते हैं लेकिन उनके समूह भी छोटे हैं। व्यापक स्तर पर यह समझ लोगों में बनी हुई है कि अवामी लीग सत्ता में बनी रहेगी। ऐसे चुनाव आयोजित करके उन्होंने (शेख हसीना ने) एक प्रणाली के रूप में चुनाव, एक संगठन के रूप में चुनाव आयोग और विचार के तौर पर लोकतंत्र के विचार को प्रभावी तौर पर कमजोर कर दिया है। इन राजनीतिक विश्लेषकों की चिंता जायज है। लोकतंत्र एक बहुदलीय या बहुध्रुवीय व्यवस्था है जिसे एक दलीय नहीं बनाया जा सकता। बांग्लादेश में ऐसा है भी नहीं। दर्जनभर छोटे दल तो मैदान में उतरते ही हैं इसके अलावा बड़ी संख्या में निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं। लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के न होने से पक्ष विपक्ष के बीच वैसा राजनीतिक टकराव नहीं होता जो लोकतंत्र को जीवंत बनाता है। इसके लिए शेख हसीना की अवामी लीग से अधिक दोषी खालिदा जिया और उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। उनको चुनाव लड़ने से किसी ने नहीं रोका है। वो अपनी ओर से लगातार चुनावों का बहिष्कार कर रही हैं क्योंकि वो एक ऐसे समावेशी बांग्लादेश की पक्षधर नहीं हैं जिसके प्रशासन का आधार इस्लाम नहीं बल्कि सेकुलर कानून हों। वो बांग्लादेश को एक कट्टरपंथी इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती हैं जिसे दुनिया में पाकिस्तान के अलावा शायद ही कोई और पसंद करेगा। शेख हसीना के कार्यकाल में उनकी यह मंशा पूरी होती नहीं दिख रही इसलिए खालिदा जिया चुनावों का ही बहिष्कार करके बैठ गयी हैं।

जबकि दूसरी ओर अवामी लीग ने समावेशी बांग्लादेश, पड़ोसियों से बेहतर रिश्ता और सेकुलर शासन व्यवस्था को महत्व दिया है। अब तक जो चुनाव परिणाम आये हैं उसमें उनकी पार्टी से 9 अल्पसंख्यक हिन्दू उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। उनकी इस नीति के कारण बांग्लादेश के कम्युनिस्ट भी उनके ग्रैंड एलायंस का हिस्सा हैं। फिर यह समझना सचमुच मुश्किल है कि बांग्लादेश के आमचुनाव को विपक्ष विहीन बतानेवाले लोग इसका दोष अवामी लीग को क्यों दे रहे हैं? अगर कोई दोषी है तो वह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जो अपनी कट्टरपंथी और कम्युनल नीति को सफल होता न देख आम चुनावों से ही अलग हो जाती है।

आज का इतिहास

1863 पहला अंडरग्राउंड रेलवे लंदन में खोला गया।
1901 टेक्सास ऑयल बूम के पहले महान गशर की खोज अमेरिका के टेक्सास के ब्यूमोंट के पास स्पिंडलेटटॉप तेल क्षेत्र में की गई थी।
1927 साइंस फिक्शन फिल्म मेट्रोपोलिस, जो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित है, जर्मनी में जारी की गई थी।
1929 बेल्जियम के कलाकार हेर्गे द्वारा बनाई गई लोकप्रिय कॉमिक किताबों की एक श्रृंखला द एडवेंचर्स ऑफ टिनटिन, पहली बार बेल्जियम के अखबार ले विन्गिएमे सिएल के बच्चों के पूरक में दिखाई दी।
1941 ग्रीको-इतालवी युद्ध- ग्रीक सेना ने अल्बानिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्लिसुरा पास पर कब्जा कर लिया।
1946 लंदन में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक में 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
1954 ब्रिटेन का कॉमेट जेट भूमध्यसागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विमान में सवार सभी 35 लोग मारे गए थे। कॉमेट दुनिया का पहला जेट विमान था जिसे ब्रिटेन ने बनाया था।
1985 सर क्लाइव सिंक्लेयर ने सिंक्लेयर सी 5 व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन, युद्ध के बाद के ब्रिटिश उद्योग के महान विपणन बमों में से एक को लॉन्च किया, जो बाद में एक कल्ट कलेक्टर का आइटम बन गया।
1993 उत्तरी अटलांटिक में अब तक दर्ज सबसे मजबूत अतिरिक्त चक्रवात ब्रेयर स्टॉर्म अपनी चरम तीव्रता पर पहुँच गया।
1996 इजरायली सरकार ने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त कर दिया।
1997 इटली द्वारा जारी 1000 लियर का नया सिक्का जर्मनी को मानचित्र पर विभाजित करता है।
2003 शिकागो पुलिस के जासूस जॉन बर्ज को 200 से अधिक संदिग्धों से जबरन कबूल करने के लिए खोजा जाने के बाद, इलिनोइस के गवर्नर जॉर्ज रयान ने 167 कैदियों की मौत की सजा सुनाई और चार और माफ कर दिए।
2004 स्वीडन के क्नुत के गाँव के पुजारी हेल्गे फ़ॉस्मो ने अपनी पत्नी और उसके पड़ोसी की हत्याओं को अंजाम दिया, जिसने देश को झकझोर कर रख दिया।
2007 एक सामान्य हड़ताल, राष्ट्रपति लांसाना कॉन्टेटो को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने का प्रयास, जिसके परिणामस्वरूप अंतत: दो नए प्रधान मंत्री की नियुक्ति हुई, जो गिनी में शुरू हुआ।
2010 चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। इसने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है।

जानें फायदे और योगासन करने का सही तरीका

अगर आप भी अपने बिजी लाइफस्टाइल की वजह से अकसर तनाव से घिरे रहते हैं तो मकरासन को अपने रूटिन का हिस्सा बना लें।

स्ट्रेस की छुट्टी करके दिमाग को शांत रखता है मकरासन

आजकल की भागती-दौड़ती जिंदगी में तनाव लोगों के जीवन का एक हिस्सा बनकर रह गया है। जिससे निजात पाने के लिए वो कई तरह के उपाय भी आजमाते हैं। लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। अगर आप भी अपने बिजी लाइफस्टाइल की वजह से अकसर तनाव से घिरे रहते हैं तो मकरासन को अपने रूटिन का हिस्सा बना लें। मकरासन संस्कृत के दो शब्द मकर और आसन से मिलकर बना है। मकर का अर्थ मगरमच्छ और आसन का मतलब पोज यानि पॉश्चर से होता है। अंग्रेजी में इस आसन को क्रोकोडाइल पोज भी कहा जाता है। मकरासन का नियमित अभ्यास व्यक्ति के अंगों को रिलैक्स करके मन को शांत रखने में मदद करता है। जिससे व्यक्ति को बैचेनी,डिप्रेशन,उलझन और माइग्रेन जैसी समस्या में राहत मिलती है।

मकरासन करने का तरीका

मकरासन करने के लिए सबसे पहले किसी खुली जगह पर अपना योगा मैट बिछाकर उसपर पेट के बल लेट जाएं। इसके बाद अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर टिकाते हुए अपना सिर और कंधे को ऊपर की तरफ ले जाएं। हथेलियों का स्टैंड बनाकर इस पर ठुड्डी को रखकर गहरी सांस लें और छोड़ें। अगर इस आसन को करते समय कमर पर ज्यादा जोर पड़ रहा हो तो कोहनियों को हल्का और फैला दें। अब धीरे-धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हुए धीरे-धीरे नीचे से ऊपर लेकर जाएं। यह एक चक्र होता है, इस तरह से आप दस चक्र कर सकते हैं।

मकरासन करने के मिलते हैं ये फायदे-

पेट की समस्या करें दूर

नियमित रूप से मकरासन का अभ्यास करने से पाचन तंत्र बेहतर होता है। इस आसन का नियमित अभ्यास थकावट और बदन दर्द को दूर करके पेट की मांसपेशियों को टोन करके कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है। जिससे पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियां दूर हो सकती हैं।

सांस संबंधी समस्या

मकरासन श्वांस संबंधी दमा जैसी परेशानियों से निजात दिलाने में मदद कर सकता है। मकरासन करते समय श्वास लेने और छोड़ने की वजह से व्यक्ति के फेफड़े मजबूत बनते है। स्वच्छ वायु अंदर लेने से छाती तंदुरुस्त रहती है जिससे श्वास संबंधी बीमारियों में लाभ मिल सकता है।

तनाव होता है दूर

मकरासन करने से हाइपरटेंशन व मानसिक रोगों से राहत मिलती है। इसके नियमित अभ्यास से तनाव दूर होने के साथ मन को शांत और एकाग्र बनाए रखने में मदद मिलती है। जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, वे इस आसन को करेंगे तो उन्हें फायदा मिलेगा। ये आसान करने में बेहद सरल है कि कोई भी व्यक्ति आसन से कर सकता है।

पीठ दर्द से राहत

अगर आप पीठ दर्द से परेशान रहते हैं तो इस आसन को जरूर करें। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाकर तनाव कम करता है। शरीर की मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं से निजात दिलाने के साथ स्लिप डिस्क जैसी समस्या को खत्म करता है। रीढ़ और कंधों की मांसपेशियों से भी तनाव कम करता है।

ठंड के मौसम में कपड़ों से आने लगी है बदबू, तो निपटने के लिए अपनाएं ये तरीके

ठंड के मौसम में खिली हुई धूप देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। अब धूप ना निकलने पर लोगों को सबसे बड़ी समस्या कपड़े सुखाने को लेकर होती है। ठंड के कपड़े मोटे होते हैं, इसलिए इनको धूप की भी ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में जब कपड़े ठीक से नहीं सूखते हैं तो बदबू की समस्या होने लगती है। कपड़ों से आ रही बदबू की वजह से उन्हें पहनना काफी मुश्किल होता है। इस बदबू से निपटने के लिए आप इन तरीकों को अपना सकते हैं।

कपड़ों से आ रही बदबू से कैसे निपटें

धोने से पहले अपनाएं ये तरीका

गीले कपड़ों में अक्सर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। जिसकी वजह से बदबू आना आम बात है। ऐसे में धुले हुए कपड़े और धोने वालों कपड़ों को एक साथ इकट्ठा ना करें। धोने से पहले कपड़ों को हवा लगने दें।

बेकिंग सोडा का करें यूज

बदबू को ऑब्जर्व करने में बेकिंग सोडा का आएगा। बदबू आने पर रात में कपड़े पर बेकिंग सोडा छिड़कें और उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। फिर सुबह अच्छी तरह से झाड़ें और कुछ देर हवा में सुखाएं।

कपड़े धोने में ये चीजें आएंगी काम

वाशिंग मशीन में कपड़ों को साफ करते समय आप उसमें गुलाब जल, जैस्मिन ऑयल या फिर कोई अपनी पसंद के सेंटेड ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे कपड़ों में अच्छी खुशबू आएगी।

सही तरह से सुखाएं कपड़े

जब धूप ना निकले तो कपड़ों को घर पर ही सुखाने की कोशिश करें। आप घर के अंदर रस्सी लगाएं और फिर कपड़ों को सुखाएं। आप चाहें तो एक कमरे में पंखा चलाकर कपड़ों को फैला सकते हैं। इससे वह जल्दी सूख जाएंगे और बदबू भी नहीं आएगी।

हल्दी पानी बदल देगी काया, जानें इसे पीने का सही तरीका

हल्दी के फायदे के बारे में तो बहुत सुना होगा। ये एंटी ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने के साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करती है। साथ ही हल्दी को स्किन पर भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सर्दियों में हल्दी वाले दूध को पीने के फायदे भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप हल्दी के ज्यादा से ज्यादा फायदे लेना चाहते हैं तो इसे कंज्यूम करने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए जानें हल्दी को पीने का सही तरीका और हल्दी पीने के फायदे।

क्या है हल्दी को कंज्यूम करने का सही तरीका

आमतौर पर घरों में रोजाना हल्दी को खाने में डाला जाता है। लेकिन शरीर को पर्याप्त मात्रा में हल्दी की मात्रा नहीं मिल पाती है। इसलिए हल्दी का पानी पीना ज्यादा फायदेमंद है। हल्दी में करक्यूमिन बायोएक्टिव कंपाउड होता है। जो शरीर के सिस्टम में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की समस्या को खत्म करता है। साथ ही स्किन को एजिंग से बचाता है।

जानें कैसे बनाएं हल्दी पानी

हल्दी का पानी पीने के लिए इसे सही तरीके से बनाएं। तो ये वेट लॉस में भी मदद करता है। हल्दी का पानी बनाने के लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर को एक गिलास पानी में भिगोकर रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह इस पानी को उबालकर आधा कर लें। जब ये आधा हो जाए तो थोड़ी सी सौंफ डाल लें। फिर इस पानी को पूरी तरह से ठंडा करें और ऑर्गेनिक शहद मिलाकर पिएं। इस पानी को पीने से शरीर को काफी सारे फायदे होते हैं।

वेट लॉस में मददगार

हल्दी का पानी रोजाना पीने से पेट के आसपास जमा फैट को गलाने में मदद मिलती है। साथ ही ओवरऑल बॉडी फैट भी घटता है।

जिन महिलाओं के शरीर में हार्मोंस इंबैलेंस की समस्या होती है। उन्हें हल्दी पानी पीने से फायदे होते हैं। हल्दी पानी पीने से पीसीओएस, पीसीओडी और थायराइड की समस्या में राहत मिलती है।

गठिया में आराम

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एंटी इंफ्लेमेटरी गुण लिए होता है। अगर हल्दी पानी को पिया जाए तो ये शरीर में होने वाली सूजन से राहत देता है। जिन लोगों को गठिया और घुटने में दर्द की शिकायत है। हल्दी पानी इस तकलीफ को कम करता है।

ब्लॉटिंग की समस्या होगी खत्म

सूजन की वजह से ब्लॉटिंग की समस्या होती है। हल्दी पानी डाइजेशन को सही करने के साथ आंतों की लाइनिंग में हो रही सूजन को खत्म करता है। जिससे ब्लॉटिंग की दिक्कत में राहत मिलती है।

डेंगू में फटाफट रिकवरी के लिए इन फूड्स को डाइट में करें शामिल, दूर होगी कमजोरी

कई बार डेंगू जानलेवा बीमारी साबित होती है। इस बीमारी के वजन तेजी से घट जाता है। ऐसे में आप अपना वेट मेनटेन रखने के लिए कुछ आसान टिप्स अपना सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो कर आप जल्द डेंगू जैसी बीमारी से रिकवर हो जाएंगे। डेंगू बीमारी मच्छर के काटने से होती है। वहीं यह बीमारी कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती है। वहीं डेंगू के लक्षणों को पूरी तरह से ठीक होने में काफी समय लगता है। हांलाकि दवाओं के जरिए इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। इस बीमारी से शरीर में कई तरह की गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। इनमें से एक समस्या है कि इस बीमारी के बाद वेट कम होने लगता है। क्योंकि डेंगू के दौरान शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। जिसके कारण तेजी से वजन घटने लगता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको डेंगू के बाद रि?कवरी और हेल?दी वजन को मेनटेन रखने के आसान टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

ऐसे मेनटेन करें वेट- इस बीमारी के बाद वजन को मेनटेन करने के लिए डाइट में हेल्दी फैट्स जैसे पीनट बटर और एवोकाडो जैसी चीजें शामिल करें।

इसके अलावा प्रोटीन रिच फूड्स को भी अपनी डाइट में शामिल करें।

रोजाना वॉक करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी भूख बढ़ेगी।

तनाव न लें। इस तरह से भी आप हेल्दी वेट मेनटेन कर पाएंगे।

इसके साथ ही एक ही समय में नाश्ता, लंच और डिनर करें। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा।

जानिए कैसे करें रिकवरी

डेंगू बीमारी से जल्दी रिकवरी के लिए केला, चावल और सूखे मेवे का सेवन करें।

काजू, मूंगफली, किशमिश और बादाम को अपनी डाइट में शामिल करें।

डाइट में पीनट बटर को शामिल करने से आप वेट मेनटेन कर पाएंगे।

इसके अलावा डाइट में केले को शामिल करें। क्योंकि केले में कार्ब्स, कैलोरीज और खनिज पदार्थ शामिल होते हैं। जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है।

हेल्दी वेट को मेनटेन करने के लिए अंडे को अपनी डाइट में शामिल करें। क्योंकि अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है।

बच्चों से लेकर बड़ों में कब्ज की समस्या का इलाज है हरड़, जानें खाने का तरीका

आयुर्वेद में कई सारी औषधियों का इस्तेमाल कब्ज की समस्या से निजात दिलाने में मदद करता है। इन्हीं में से एक है हरड़। खासतौर पर सर्दियों के मौसम में जब लोग कम फिजिकल एक्टिव रहते हैं तो कब्ज की दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसे में हरड़ का इस्तेमाल इससे राहत दिला सकता है। केवल बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में होने वाली कब्ज के लिए भी हरड़ को खिलाया जा सकता है। जानें हरड़ खाने का तरीका और इससे होने वाले फायदे।

पेट से जुड़ी बीमारियों में आराम

कब्ज, पेट फूलना, अपच जैसी पाचन की दिक्कतों में हरड़ खाना फायदेमंद होता है। साथ ही हरड़ गैस की समस्या को भी खत्म करती है। हरड़ को इन तरीकों से खाना पेट के लिए फायदेमंद होता है।

हरड़ खाने के फायदे

हरड़ में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। साथ ही इसे खाने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है। वहीं हरड़ टेस्ट बड्स को संतुष्टि देते हैं। इसमे आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मैग्नीशियम, प्रोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। हरड़ खाने से इन बीमारियों में आराम मिलता है।

हरड़ का पाउडर

पीली हरड़ को भूनकर उसका पाउडर बनाकर रख लें। रात को सोते वक्त इस पाउडर को गुनगुने पानी के साथ पीने से कब्ज की समस्या से आराम मिलता है।

- वहीं बच्चों को सर्दी में कफ लगातार बनी है और खत्म नहीं हो रही तो उसके कब्ज को दूर करने के लिए पीली हरड़ के पाउडर को शहद में मिलाकर या पानी में दिया जा सकता है।
- 3 साल से ऊपर के बच्चों को पीली हरड़ को घिसकर इसके थोड़े से पेस्ट को देने से बच्चों में कब्ज के साथ ही भूख ना लगने की समस्या भी खत्म होती है।
- कब्ज के साथ अपच, ब्लॉटिंग जैसी समस्याओं को खत्म करना है तो काली छोटी हरड़ को खाना खाने के बाद चूसें। इससे डाइजेशन सही रहता है।

पोषण और स्वाद से भरपूर हैं डेट बार, नोट कीजिए इनकी रेसिपी और फायदे

चॉकलेट के हेल्दी विकल्प जैसे प्रोटीन बार या कुछ और ढूंढते हुए या खाते हुए आप भी बोर हो गए हैं, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम आपके लिए एक हेल्दी और टेस्टी बार की रेसिपी लेकर आए हैं। जिसे खाने के बाद आपको बिल्कुल भी गिल्ट महसूस नहीं होने वाला है। आज आपको बताते हैं डेट बार की रेसिपी । ये रेसिपी बनाने में बहुत आसान है और आपको इसे खाने से फुल एनर्जी मिलेगी।

पहले जानते हैं खजूर के फायदे

गट हेल्थ के लिए फायदेमंद- खजूर फाइबर से भरपूर होता है जिसके कारण ये गट हेल्थ को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह हेल्दी गट माइक्रोबायोम से लेकर कई पूरानी बिमारियों के जोखिम को कम करने मदद करता है। खजूर में उच्च फाइबर और पॉलीफेनोल होने के कारण कोलन कैंसर को कम कर सकता है।

हड्डियों को मजबूत करता है- दूध को हड्डियों को मजबूत करने के लिए काफी पसंद किया जाता है क्योंकि उसमें कैल्सीयम होता है। लेकिन अगर आप वीगन है तो इसमें खजूर आपकी मदद कर सकता है। खजूर फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम कई खनिजों का स्रोत है जो हड्डियों को मजबूत करते है। वे विटामिन च का भी स्रोत हैं जो स्वस्थ, मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी है।

ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है- यदि आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप आराम से बिना किसी डर के इसका सेवन कर सकते है। खजूर में प्राकृतिक शर्करा होती है। एक मध्यम आकार के खजूर में लगभग 6 ग्राम चीनी होती है। लेकिन, यह फाइबर से भी भरपूर होता है। यह फाइबर रक्त शुगर के रिलीड को कंट्रोल करता है। जिससे आपके ब्लड शुगर लेवल नें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है।

थकान को कम करता है-यदि आप खजूर का सेवन करते है तो ये थकान से लड़ने और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में आपकी बहुत मदद करता है। सर्दियों में अलग आप खजूर का सेवन करते है तो ये आपको कफ और सर्दी से बचाने में मदद करेगा। ये एथलीटों को भी अच्छी ऊर्जा प्रदान कर सकता है।

खजूर अमीनो एसिड से भरपूर होता है- खजूर में ऐलेनिन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, सेरीन या वेलिन जैसे अमीनो एसिड भी होते हैं। इन अमीनो एसिड में कई गुण होते हैं, जैसे रक्तचाप या जोड़ों के दर्द को कम करना। ये आपकी मांसपेशियों को बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकते है।

चलिए अब जानते हैं कैसे बनाएं खजूर की चॉकलेट

- डेट्स बार बनाने के लिए आपको चाहिए
- खजूर 1 कप, कटा हुआ
- मेवे (बादाम, अखरोट, या मिश्रित), कटे हुए 1 कप
- रोल्ड ओट्स 1 कप
- शहद या मेपल सिरप स्वादानुसार
- पीनट बटर 1/4 कप
- वेनिला एसेंस 1 चम्मच
- नमक की चुटकी
- टॉपिंग के लिए चॉकलेट चिप्स, सूखे ड्राई फ्रूट्स (वैकल्पिक)

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

आस्था दिखाएं, गुस्सा नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के दिन रहे सचेतः मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में अपने मंत्रियों को सख्त संदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर को लेकर पार्टी नेताओं और मंत्रियों से संयमित रहने को कहा है। साथ ही साथ उन्हें फालतू बयानबाजी ना देने की बात कही है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि 22 जनवरी को आपको सचेत रहना है। आपको आस्था दिखाना है ना कि गुस्सा। उन्होंने कहा कि सरकार की मर्यादा को आप लोग बनाए रखें। पीएम नेताओं को बयान बाजी से बचने की नसीहत है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इस बात का ध्यान रखें। 22 जनवरी के बाद लोगों को राम मंदिर का दर्शन कराए। अपने इलाके के लोगों को राम मंदिर लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य प्रतिष्ठा समारोह का देश भर में बूथ स्तर पर सीधा प्रसारण करने की तैयारी में है। यह समारोह 22 जनवरी, 2024 को होने वाला है।

राहुल को देश में गंभीरता से नहीं लिया जाता : भाजपा

नईदिल्ली। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर भाजपा का हमला जारी है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को हमारे देश में गंभीरता से नहीं लिया जाता। वह यात्रा में तरह-तरह की टिप्पणियां करेंगे जिससे सबका मनोरंजन होगा और साथ ही कांग्रेस पार्टी का उपहास भी उड़ेगा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिस तरह से वे तीन राज्यों में हार गए हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को उन पर भरोसा नहीं है और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर रहे हैं, और जिस तरह से कांग्रेस धीरे-धीरे खुद को इंडिया गठबंधन से खोती जा रही है और यह निश्चित रूप से राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने और उनकी ब्रांडिंग करने और कांग्रेस पार्टी को फिर से स्थापित करने की यात्रा है। भाजपा नेता ने दावा किया कि केसी त्यागी का कहना है कि भारत न्याय यात्रा निकाली जानी चाहिए थी, मेरी राय में, इंडिया गठबंधन में मतभेदों को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा समय की मांग है।

नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी ने चार्जशीट दायर किया

नईदिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरोप पत्र दायर किया। आरोपपत्र में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, हृदयानंद चौधरी और अमित कात्याल के नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आरोपपत्र में दो फर्मों को आरोपी के रूप में नामित किया गया है। अदालत के निर्देश के अनुसार, ईडी को मंगलवार तक ही आरोपपत्र और दस्तावेजों की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति (ई-कॉपी) दाखिल करनी है और मामले पर 16 जनवरी को संज्ञान लिया जाना है। अमित कात्याल कथित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख से जुड़े हैं। लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में जांच एजेंसी ने हिरासत में लिया था। कथित घोटाले की उत्पत्ति उस समय से होती है जब लालू प्रसाद यूपीए-1 कैबिनेट में केंद्रीय रेल मंत्री थे।

जब तक जिंदा हूं, समाज में बंटवारा नहीं होने दूंगी : ममता

कोलकाता। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से उपस्थित हो रहे हैं। हालांकि, इसको लेकर राजनीति भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए भाजपा नौटंकी कर रही है। जयनगर में कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा, मैं धार्मिक आधार पर जनता को बांटने में विश्वास नहीं करती। ममता ने साफ तौर पर कहा कि जब तक जिंदा हूं, समाज में बंटवारा नहीं होने दूंगी। उन्होंने कहा कि मैं उन उत्सवों में विश्वास करती हूं जो सभी समुदायों के लोगों को साथ लेकर चलते हैं और एकता की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इसे (राम मंदिर उद्घाटन) अदालत के निर्देश के तहत कर रही है। उन्होंने दावा किया कि हम भाजपा के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।

शिवसेना विधायक अयोग्यता केस में आई फैसले की घड़ी

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामले में अपना फैसला सुना सकते हैं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की 10 जनवरी की समय सीमा समाप्त हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने की समयसीमा 31 दिसंबर 2023 तय की थी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन की मोहलत दे दी थी। जून 2022 में शिंदे और कई विधायकों ने तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिससे शिवसेना में विभाजन हो गया, जिसके कारण सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी सरकार गिर गई, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस भी शामिल थी। सूत्रों के मुताबिक, शिवसेना के दोनों गुटों द्वारा दायर 34 याचिकाओं पर आधारित फैसला स्पीकर द्वारा छह भागों में पढ़ा जाएगा। शिंदे और ठाकरे दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है।

पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी मामला : एनसीपी की मालदीव सरकार को फटकार

हम देश के बाहर से प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे : शरद पवार

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मालदीव के सांसद की आपत्तिजनक टिप्पणी अब मालदीव सरकार पर भारी पड़ रहा है। भारत की ओर से लगातार पलटवार किया जा रहा है। इसी कड़ी में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और मालदीव सरकार की आलोचना की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और अगर किसी अन्य देश का कोई व्यक्ति, जो किसी भी पद पर है, हमारे प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी करता है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमें पीएम के पद का सम्मान करना चाहिए। हम देश के बाहर से प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे।

इसके साथ ही उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर भी अपनी बात रखी। पवार ने कहा कि यह शुरुआती बैठक है और आज की बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। जब कई पार्टियां एक साथ आती हैं तो आक्रामक मांगें की जाती हैं लेकिन सभी को मिलकर ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जो उस राज्य में काम करे जहां उनका प्रभुत्व नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को खारिज करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि एमवीए में सीटों का बंटवारा आसान होगा... सीटों का बंटवारा योग्यता के आधार पर किया जाएगा और एमवीए को सभी सीटों पर बीजेपी को हराना है, जिसके लिए पूरी योजना तैयार है।

लक्षद्वीप के लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल ने द्वीपसमूह की पर्यटन संभावनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए पोस्ट पर मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी की सोमवार को निंदा की। उन्होंने कहा कि वे भारत की आंतरिक मामलों को लेकर टिप्पणी करने से पहले दो बार सोचें। फैजल ने कहा, ''माननीय प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप के पर्यटन को लेकर की गई टिप्पणी पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला था। मालदीव के उप मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणी अवांछित और

बेतुकी थीं।'' मालदीव की सरकार ने मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर तीन उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया था।

मालदीव विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष का बयान
प्रधानमंत्री हर चीज को निजी तौर पर ले रहे हैं

बेंगलुरु। भारत-मालदीव विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए खरगे ने कहा कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद हर चीज को निजी तौर पर ले रहे हैं। खरगे ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। हमें समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते।

मालदीव के उप मंत्री, अन्य कैबिनेट सदस्यों और सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक और अरुचिकर संदर्भ देने के बाद एक बड़ा विवाद शुरू हो गया। पीएम मोदी ने 2 जनवरी को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का दौरा किया और कई तस्वीरें साझा कीं, जिसमें स्नॉर्कलिंग में हाथ आजमाने का एक रोमांचक अनुभव भी शामिल था।

एक्स पर पोस्ट में पीएम मोदी ने सफेद समुद्र तटों, प्राचीन नीले आसमान और समुद्र की तस्वीरें साझा कीं और उन्हें एक संदेश के साथ टैग किया, जिसमें लिखा था, न लोगों के लिए जो उनमें साहसिकता को अपनाना चाहते हैं, लक्षद्वीप जरूर शामिल होना चाहिए। भारत में मालदीव के दूत को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और तीन निलंबित मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी कड़ी चिंताओं से अवगत कराया।

सरकार का बड़ा फैसला, लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी

नई दिल्ली। मालदीव के साथ जारी विवाद के बीच एक अहम खबर सामने आई है। दरअसल भारत सरकार लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर नया एयरपोर्ट बनाने की योजना बना रही है। इस एयरपोर्ट के बनने से लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है। खास बात ये है कि नया एयरपोर्ट नागरिक उद्देश्य के साथ ही सैन्य उद्देश्य के लिए भी होगा और यहां से नागरिक विमानों के साथ ही सैन्य विमान भी संचालित हो सकेंगे। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि नए एयरपोर्ट पर नागरिक विमानों के साथ ही सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान और फाइटर जेट्स भी संचालित हो सकेंगे और यह एक संयुक्त एयरफील्ड होगा। सरकार ने पहले भी मिनिकॉय द्वीप पर नया एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब इस प्रस्ताव में बदलाव कर इसे संयुक्त एयरफील्ड के रूप में विकसित करने की तैयारी है। सैन्य दृष्टि से नए एयरपोर्ट के बनने से भारत को अरब सागर और हिंद महासागर में निगरानी करने में रणनीतिक रूप से काफी मदद मिलेगी। भारतीय तटरक्षक बल ने पहले सरकार को मिनिकॉय द्वीप पर हवाई पट्टी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन अब ताजा प्रस्ताव में भारतीय वायुसेना को यहां प्रमुख तौर पर संचालन दिया जाएगा।

केजरीवाल के बंगले पर आरटीआई दिखा भाजपा का आरोप

दिल्ली के विकास की कीमत पर हुआ व्यक्तिगत विकास

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर किए गए कार्यों की लागत की मांग करने वाली एक आरटीआई की प्रति साझा करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक पर दिल्ली के विकास की कीमत पर व्यक्तिगत विकास करने का आरोप लगाया। पात्रा ने आरटीआई की कॉपी एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा यह सबूत है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विकास की कीमत पर अपना व्यक्तिगत विकास चाहते हैं। दिल्ली सरकार से प्राप्त आरटीआई जवाब से पता चलता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर केवल सिविल कार्यों पर 29,56,35,074/- रुपये खर्च किए गए थे।

यह जानकारी महाराष्ट्र निवासी अजय बासुदेव बोस ने मांगी थी। अपने आवेदन में, बोस ने दिनांक 31 मार्च 2015 से 27 दिसंबर 2022 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर सिविल, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, सीवेज, बढ़ईगीरी कार्यों पर खर्च की गई राशि की जानकारी मांगी थी। आवेदन का जवाब देते हुए आरटीआई में कहा गया है कि 2015 से 2022 की अवधि के दौरान किया गया कुल व्यय केवल सिविल कार्यों के लिए 295635074/- रुपये है। उन्होंने 31 मार्च 2015 से 27 दिसंबर 2022 तक काम के लिए नियुक्त ठेकेदारों के नाम और उन्हें भुगतान की गई राशि के बारे में भी पूछा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरटीआई पोस्ट करते हुए एक्स पर कहा, %केजरीवाल के शीशमहल में करोड़ों के पर्दे, लाखों की टॉयलेट सीट और अश्लील खर्च है। यहां तक कि केवल सिविल कार्यों पर भी केजरीवाल ने लगभग 30 करोड़ खर्च किए। ये है आम आदमी! कांग्रेस और बीजेपी विधायक केजरीवाल पर अपने सरकारी आवास के नवीनीकरण पर करोड़ों रुपये

खर्च करने का आरोप लगाते रहे हैं। भाजपा केजरीवाल और आप की आलोचना करते हुए आरोप लगा रही है कि 2020-22 के बीच 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री के आवास के नवीनीकरण के लिए 45 करोड़ का उपयोग किया गया था। इसके जवाब में आप ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा इस मुद्दे को तूल देकर वास्तविक चिंताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

राहुल गांधी की झारखंड यात्रा की तैयारी में जुटे कांग्रेसी

नईदिल्ली। राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' की तैयारी झारखंड में जोर-शोर से चल रही है। इसी तैयारी के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची आ रहे हैं। 11 जनवरी को सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई है। रांची के मोरहाबादी स्थित संगम गार्डेन में होने वाली इस बैठक में प्रदेश प्रभारी जीए मीर मौजूद रहेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने मंगलवार (नौ जनवरी) को यह जानकारी दी। मुंजनी ने बताया कि राहुल गांधी 14 जनवरी को 6700 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत इंफाल से करेंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

शमी सहित 16 अन्य खिलाड़ियों को राष्ट्रपति ने दिया अर्जुन पुरस्कार

नईदिल्ली। दिल्ली में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी को पुरस्कार दिया गया। मोहम्मद शमी और को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अर्जुन पुरस्कार मिला। ओजस प्रवीण देवताले को भी अर्जुन पुरस्कार मिला।

भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जहां क्रिकेटर मोहम्मद शमी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पहुंचे। बैडमिंटन खिलाड़ियों चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी को 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्होंने 2023 में एशियाई खेलों में अपना और बैडमिंटन में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा एशियाई चैंपियनशिप और इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 का खिताब भी जीता। यह पुरुष जोड़ी वर्तमान में मलेशिया ओपन सुपर 1000 में खेल रही है और इसलिए समारोह में शामिल नहीं हुई।

हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आम तौर पर 29 अगस्त को होने वाले खेल पुरस्कार समारोह को पिछले साल 23 सितंबर से आठ अक्टूबर तक हुए हांगझोउ एशियाई खेलों के कारण स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रपति भवन में समारोह में 26 खिलाड़ियों और पैरा खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिछले साल दुनिया की नंबर एक जोड़ी बनने वाले चिराग और सात्विक की नजरें पेरिस ओलंपिक पर टिकी हैं। फिलहाल दूसरी विश्व रैंकिंग पर काबिज इस जोड़ी का इस साल होने वाले पेरिस खेलों के लिए क्वालीफाई करना लगभग तय है। टखने की चोट से उबर रहे शमी सम्मान हासिल करने के लिए समारोह में मौजूद थे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 30 अंक चढ़कर बंद निफ्टी 21500 के पार

नई दिल्ली। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव दिखा। मंगलवार को कारोबारी सेशन के बाद घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर बंद होने पर सफल रहे हालांकि उन्होंने अपने दिनभर की बढ़त गंवा दी। मंगलवार को बाजार में पूरे दिन मजबूती बनी रही पर आखिरी सेशन में बड़ी बिकवाली के कारण सेंसेक्स और निफ्टी ने मजबूती गंवा दी और मामूली बढ़त के साथ ही बंद हो पाए। मंगलवार को सेंसेक्स 30.99 (0.04 प्रतिशत) अंकों की बढ़त के साथ 71,386.21 के स्तर पर जबकि निफ्टी 31.85 (0.15 प्रतिशत) अंकों की मजबूती के साथ 21,544.85 के लेवल पर बंद हुआ।

जेनसोल इंजी. गुजरात में 2000 करोड़ का करेगी निवेश

नईदिल्ली। जेनसोल इंजीनियरिंग गुजरात में ईवी विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के लिए निवेश प्रोत्साहन गतिविधि के हिस्से के रूप में गुजरात सरकार के साथ इस आशय के एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना से करीब 1500 नौकरियों का सृजन होगा। जेनसोल समूह के सह-संस्थापक अनमोल सिंह जग्गी ने कहा, '' 2,000 करोड़ रुपये का निवेश राज्य की निरंतर वृद्धि और हरित विनिर्माण के प्रति प्रतिबद्धता में हमारे विश्वास का प्रमाण है। हम पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी की उम्मीद करते हैं जो गुजरात को ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) क्रांति में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।''

बजाज ऑटो का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपये के पार

नईदिल्ली। बजाज ऑटो का मार्केट कैप पहली बार 2 ट्रिलियन रुपये के स्तर पर पहुंच गया। मंगलवार के इंट्राडे कारोबार में बीएसई पर दोपहिया और तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी का स्टॉक 6 प्रतिशत बढ़कर 7,420 रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। बजाज ऑटो के शेयरों में यह उछाल बोर्ड की तरफ से 10,000 रुपये प्रति शेयर पर 4,000 करोड़ रुपये के शेयर बायबैक को मंजूरी देने के ऐलान के बाद आया है। पिछले एक साल में बजाज ऑटो के शेयर ने 105 प्रतिशत के उछाल के साथ बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी तुलना में इस अवधि के दौरान एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 18 फीसदी और एसएंडपी बीएसई ऑटो इंडेक्स 43 फीसदी चढ़ा है। शेयर की कीमतों में आज तेजी के बाद बजाज ऑटो का मार्केट कैप आज इंट्राडे कारोबार में 2 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा हो गया।

राम मंदिर के भव्य निर्माण से अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार

लखनऊ। भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में अयोध्या ने ऊंची छलांग लगायी है। उत्तर प्रदेश में बीते साल फरवरी में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन में जहां अयोध्या को 49000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले वहीं निर्यात के मोर्चे पर भी रामनगरी को भारी सफलता मिली है। बीते एक साल में विभिन्न क्षेत्रों में अयोध्या से 254 करोड़ रुपये की वस्तुओं की निर्यात किया गया है। इससे पहले वर्ष 2021-22 में अयोध्या से 110 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। इस तरह वर्ष 2022-23 में अयोध्या से होने वाले निर्यात में 150 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अयोध्या से सबसे अधिक निर्यात कोयले का हुआ है जबकि विभिन्न तरह के पेपर्स व आयुर्वैदिक दवाएं भी बाहर भेजी जा रही हैं।

विदेशी मुद्रा संकट के बीच राजनीतिक स्थिरता लाने शेख हसीना के लिए चुनौती

आनंद कुमार

बीते रविवार यानी सात जनवरी को बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के लिए मतदान हुआ, जिसमें शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग एक बार फिर विजयी हुई है। विश्लेषकों का मानना है कि शेख हसीना की सत्ता में वापसी भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि उनका रुख हमेशा से भारत समर्थक रहा है, जबकि बीएनपी के शासन के दौरान भारत के अलगाववादियों को वहां सुरक्षित पनाह मिलती रही है और बीएनपी का रुख भारत विरोधी रहा है।

इस राजनीतिक परिदृश्य में अचानक लोगों का ध्यान नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस की ओर चला गया, जिन्हें हाल ही में बांग्लादेश की एक श्रम अदालत ने छह महीने जेल की सजा सुनाई है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ यूनुस को ऊपरी अदालत में अपील करने की इजाजत दी गई है,

मुहम्मद यूनुस बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के माध्यम से अपने सूक्ष्म-ऋणों के लिए जाने जाते हैं। इस कार्यक्रम को बड़ी संख्या में बांग्लादेशी महिलाओं के उत्थान का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने लघु व्यवसाय शुरू किया। कुछ लोगों का मानना है कि यूनुस का कार्यक्रम उस देश के लिए चमत्कार की तरह है, जो पहले अत्यंत गरीबी के लिए जाना जाता था। मगर उनके विरोधियों का मानना है कि वह उधारकर्ताओं से भारी ब्याज वसूलते हैं, वे इसे सीधे कानूनी मामले के रूप में देखते हैं।

दूसरी तरफ, यूनुस और उनके उपक्रम ग्रामीण टेलिकॉम के तीन निदेशकों को दोषी ठहराए जाने को कुछ लोग सरकार द्वारा विरोधी आवाजों को दबाने के एक और प्रयास के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि इससे स्वतंत्रता और कम होगी। अभिव्यक्ति

की स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत और एमनेस्टी इंटरनेशनल की पूर्व महासचिव आइरिन खान ने इसे न्याय का मखौल बताया है। उनका आरोप है कि न्यायिक व्यवस्था को हथियार बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में श्रम कानूनों के उल्लंघन के कई मामले हैं, लेकिन सरकार श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए व्यवसायियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। वह कहती हैं कि यूनुस के खिलाफ मुकदमा और आरोप तुच्छ एवं हल्के प्रतीत होते हैं।

कुछ लोगों को यह भी संदेह है कि पद्मा नदी पर पुल बनाने की परियोजना के लिए विश्व बैंक के वित्त पोषण को रद्द करवाने के पीछे मुहम्मद यूनुस का हाथ था। हालांकि यह आरोप कभी साबित नहीं हो सका, लेकिन उन्हें अवामी लीग सरकार की दुश्मनी झेलनी पड़ी। पद्मा नदी पुल परियोजना को शेख हसीना सरकार की मुख्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक माना जाता है और इसने बांग्लादेश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

मुहम्मद यूनुस की सजा पर बहस हो सकती है, पर एक बात निश्चित है कि उन्हें पश्चिम में बहुत लोग पसंद करते हैं। कुछ लोगों को डर है कि उनकी सजा से बांग्लादेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। एफडीआई एक सफल विकास रणनीति का प्रमुख तत्व है, क्योंकि यह आर्थिक बदलाव लाने के लिए आवश्यक पूंजी और तकनीकी हस्तांतरण को संभव बनाता है। कई वजहों से बांग्लादेश का एफडीआई प्रवाह हमेशा काफी कम रहा है। लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार के अलावा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनका मुनाफा वापस देने से रोकने का सरकार का निर्णय उनमें से एक है।

बांग्लादेश अपने निर्यात के लिए भी पश्चिमी देशों पर बुरी तरह से निर्भर है। करीब 40 अरब डॉलर मूल्य के बांग्लादेशी निर्यात का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका एवं यूरोपीय संघ जाता है। यदि वहां हुए चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भागीदारीपूर्ण नहीं माना जाता है, तो यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इस बार बांग्लादेश के चुनाव पर पश्चिमी देशों की तीखी नजर रही। अब यह देखना है कि चुनाव के बाद बांग्लादेश राजनीतिक गतिरोध से कैसे निपटता है। यदि शेख हसीना सरकार मुल्क में राजनीतिक स्थिरता लाने में विफल रहती है, तो यह पश्चिमी देशों को नई कठिनाइयां पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो शायद बांग्लादेश को पसंद न आए, खासकर तब, जब वह विदेशी मुद्रा के संकट का सामना कर रहा है।

अमित जोगी ने की शाह से मुलाकात, क्या जेसीसीजे का बीजेपी में होगा विलय?

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी घेरेबंदी और भेंट मुलाकात की राजनीति तेज हो गई है। नई दिल्ली में सोमवार को अमित जोगी ने अमित शाह से मुलाकात की है। इस बात की जानकारी खुद अमित जोगी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर दिया है। अमित जोगी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट हुई।

छत्तीसगढ़ में सियासी चर्चाएं तेज

छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में अमित शाह और अमित जोगी के बीच हुई भेंट मुलाकात पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द अमित जोगी अब भाजपा में शामिल होंगे और उनकी पार्टी जेसीसीजे का विलय भाजपा में हो सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर न तो बीजेपी की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है और ना ही अमित जोगी

की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। इस मुलाकात के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। विलय की उड़ती उड़ती खबरों की किसी तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ कयासों का दौर चल रहा है।

अमित को लोकसभा चुनाव लड़ाने की संभावना

इस मुलाकात के बाद कई तरह के संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि अगर जेसीसीजे का बीजेपी में विलय होता है तो अमित जोगी को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। उन्हें कोरबा लोकसभा सीट दी जा सकती है। इस तरह की अटकलों पर सिर्फ चर्चा हो रही है, अभी तक इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसे लेकर किसी तरह की ना तो अमित जोगी ने जानकारी दी, न हीं पार्टी की ओर से कोई बयान जारी किया गया है। सिर्फ अमित जोगी ने अमित शाह से मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो जारी कर ट्वीट किया है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में अमित जोगी ने पाटन सीट से उस वक्त के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से विजय बघेल ने तगड़ी फाइट दी थी। अमित जोगी के चुनाव लड़ने से त्रिकोणीय मुकाबला यहां हुआ था। तभी से कांग्रेस की तरफ से जोगी कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है। कांग्रेस काफी अरसे से जोगी कांग्रेस पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रही है।

अजीत जोगी के निधन के बाद बिखरता जेसीसीजे

जब से अजीत जोगी का निधन हुआ है। तब से जेसीसीजे बिखराव के दौर से जूझ रहा है। कई बड़े नेता जेसीसीजे छोड़कर जा चुके हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में जोगी कांग्रेस को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। इससे पहले साल 2018 के चुनाव में जेसीसीजे को पांच सीटें मिली थी। अब अमित शाह से अमित जोगी के मुलाकात को लेकर जेसीसीजे के बीजेपी में विलय को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।

प्रधानमंत्री मोदी की सहृदयता से बिंझिया समाज को मिला न्याय- साय

वर्षों के प्रयास से बिंझिया समाज को मिला जनजाति का दर्जा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज सूरजपुर जिले के जमदेई में आयोजित 'अखिल भारतीय बिंझिया समाज के महासम्मेलन और अभिनंदन समारोह' को सम्बोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सहृदयता से बिंझिया जाति सहित 12 जातियों को जनजाति का दर्जा मिला। वर्षों से बिंझिया समाज जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिए मांग कर रहा था। उन्होंने कहा कि मांग के प्रति संवेदनशीलता दिखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बिंझिया समाज सहित बारह जातियों को जनजातियों की सूची में शामिल किया, इन जातियों को विकास की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिला। आज बहुत खुशी है कि बिंझिया समाज सहित 12 जातियों के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बन रहा है और शासन की योजनाओं का लाभ इन वर्गों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार, सांसद रहते हुए मैंने स्वयं और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि आज इन वंचित समुदायों को उनका हक मिला है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वे जब केंद्र में राज्यमंत्री थे। तब उन्होंने लगातार बिंझिया समाज सहित 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के लिए लगातार प्रयास किए थे। उन्होंने बताया कि लोकसभा व राज्यसभा में इस वर्ग की पीड़ा और समस्याओं को संसद में जोर-शोर से उठाया गया ताकि आदिवासी भाई-बहनों के साथ न्याय हो सके। उन्होंने 12 जातियों को जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रति आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर मां कुदरगढ़ी मंदिर में रोप वे की स्वीकृति की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने देवीपुर महामाया मंदिर से पंपापुर रोड चौड़ीकरण के लिए 4.5 करोड़ रुपए, देवीपुर से नौवापर मार्ग में जोगीगुड़ा नाले में पुलिया निर्माण के लिए 3 करोड़ रूपए की स्वीकृति, 50 सीटर बालिका छात्रावास की मंजूरी तथा जमदेई में 20 लाख रूपए की लागत से सामुदायिक भवन की स्वीकृति की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मोदी जी की गारंटी में किए गए हर वायदे को पूरा करेंगे। हमने शपथ ग्रहण करने के बाद केबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख परिवारों को पक्का मकान देने की

स्वीकृति का ऐतिहासिक निर्णय लेकर मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की शुरूआत की। दूसरा वायदा पूरा करते हुए सुशासन दिवस के अवसर पर 12 लाख से अधिक किसानों को दो वर्ष के बकाया धान बोनस की 3716 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किसानों के खाते में किया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की पत्रकारों से चर्चा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारो से चर्चा करते हुये कहा कि 14 जनवरी से न्याय यात्रा शुरू हो रही है। मणीपुर से लेकर मुम्बई तक और छत्तीसगढ़ में भी लगभग 536 से अधिक किलोमीटर होकर गुजरेगी। रायगढ़ से होकर 7 जिलो सरगुजा तक न्याय यात्रा जायेगी। कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा की जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी गयी है। 11 जनवरी को नव नियुक्त प्रभारी सचिन पायलट रायपुर आ रहे है और न्याय यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे और न्याय यात्रा के स्वागत को अंतिम रूप देंगे।

हमने आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद मीडिया के माध्यम से बधाई दिया था। भाजपा आदिवासी मुख्यमंत्री की सबसे बड़ा यह चुनौती है जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा बचाने का। देश में केन्द्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक 2 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से एक साथ मिलकर काम कर रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री बने 1 महिने से ज्यादा हो गये लेकिन सबसे ज्यादा हमला आदिवासियों के ऊपर हुआ है। हसदेव वनों की कटाई। जनवरी 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ग्राम सभा आयोजित किया गया था।

महंगाई-बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बनाती बीजेपी: बैज

जगदलपुर। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने हसदेव मामले में एक बार फिर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. दीपक बैज ने जगदलपुर में बयान देते हुए कहा कि, आदिवासी चेहरा आगे कर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से प्रदेश में रिमोट कंट्रोल के जरिए सरकार चल रही है. जगदलपुर राजीव भवन में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनके द्वारा हसदेव में जंगल की कटाई को रोकते हुए टेंडर पर रोक लगाने की मांग की जाएगी. दीपक बैज ने कहा, हसदेव मामले में कांग्रेस की सरकार से कोई गलती नहीं हुई, जबकि भूपेश सरकार ने हसदेव में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई. विधानसभा में प्रस्ताव भी पास किया और साथ ही पर्यावरण अनुमति निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की.

प्रकाश पर्व पर निकली प्रभात फेरी संघ कार्यालय पहुंची, हुआ शबद कीर्तन

रायपुर। गुरु गोविन्द सिंह जी के पावन प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा से निकली प्रभात फेरी आज मंगलवार को सुबह पंडरी स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रदेश कार्यालय %जागृति मंडल% पहुंची। संघ कार्यालय में उपस्थित सभी संघ अधिकारी, कार्यकर्ता, स्वयंसेवकों ने स्वागत तथा पूजन किया। कार्यालय के सभागार में शबद कीर्तन हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी तथा गुरु तेगबहादुर सिंह जी के जीवन प्रसंगों से जुड़े प्रेरणादायी भजन भी गाए गए इस अवसर पर संघ के अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख सुनील कुलकर्णी, क्षेत्र के सम्पर्क प्रमुख अनिल डागा, प्रान्त के अधिकारी, कार्यकर्ता स्वयंसेवक सहित नगर के परिवार जन भी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

क्षेत्र के विकास के लिए रखी विभिन्न मांग : केदार

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, सहकारिता और कौशल विकास मंत्री श्री केदार कश्यप से आज यहां उनके राजधानी रायपुर स्थित निवास में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने सौजन्य मुलाकात की।

मंत्री श्री कश्यप से ओरछा व छोटेडोंगर से आये लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। वनमंत्री श्री कश्यप ने क्षेत्रवासियों की सभी समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना और इस संबंध में आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता के हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्षेत्र की सभी समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाएगा। क्षेत्रवासियों ने इस अवसर पर बताया कि पिछले 5 वर्ष से नारायणपुर क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ गया है। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ-साथ रोजगार के लिए पहल जरूरी है।

कलेक्टर की कार्रवाई का विरोध

रायपुर। सेजेस वाड्रफनगर के संविदा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला आशीष केसरी को जिला प्रशासन बलरामपुर रामानुजगंज कलेक्टर रिमिजियुश एक्का के द्वारा नौकरी से कार्यमुक्त कर दिया गया है. आशीष केसरी पर आरोप है कि उन्होंने विद्यालय के कक्ष 5वीं और कक्षा दसवीं के बच्चों द्वारा फॉल सीलिंग को तोड़वाया है. जबकि आशीष केसरी से बात करने पर पता चला कि उन्होंने घटना की जानकारी प्राचार्य आरके सिंह को फोन कॉल के माध्यम से बताया कि कक्ष क्रमांक 5 का फॉल सीलिंग गिर गया है. जिस पर प्राचार्य आरके सिंह ने कहा कि आप प्यून से हटवा लीजिए और उसने प्यून से हटवा दिया. कुछ लोगों ने उक्त घटना का वीडियो बनाकर कलेक्टर से शिकायत कर दी. शिकायत के आधार पर जांच टीम बनाई गई. जांच टीम ने जब विद्यालय आकर बच्चों और शिक्षकों से पूछताछ की तो बच्चों ने बताया कि पंखा चालू करने से फॉल सीलिंग गिरा है. शिक्षकों ने जानकारी नहीं होने का बहाना बना दिया. कुछ शिक्षक आशीष केसरी पर आरोप लगाते हुए बोले कि बच्चों ने बताया कि आशीष केसरी के कहने पर फॉल सीलिंग गिराएं है. जांच समिति ने कुछ बच्चों के बयान को नजरंदाज करते हुए शिक्षकों के बयान जो फॉल सीलिंग गिरने के समय उपस्थित नहीं थे उनके बयान को सच मानकर आशीष को गलत बताकर रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दिया।

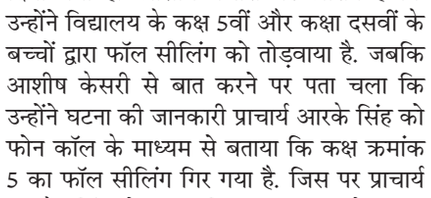

बेदरे फायरिंग की वारदात शामिल 3 नक्सली गिरफ्तार

सुकमा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर थाना जगरगुण्डा क्षेत्रान्तर्गत कैंप सिलगेर से 229 वाहिनी सीआरपीएफ, 210 वाहिनी कोबरा एवं जिला बल की संयुक्त पार्टी ग्राम तिम्मापुर, पाण्डूमेटा पहाड़ी की ओर रवाना हुए थे। अभियान के दौरान पाण्डूमेटा पहाड़ी के पास से 3 नक्सली डीएकेएमएस सदस्य मड़कम हांदा पिता नंदा निवासी पूवर्ती थाना जगरगुण्डा, मिडियम पोदिया पिता पाण्डू निवासी बेदरे थाना जगरगुण्डा तथा कोरसा धुरवा पिता पाण्डू निवासी टेकलगुड़ा पटेलपारा थाना जगरगुण्डा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तीनों नक्सलियों के नक्सल रिकार्ड की जांच करने पर थाना जगरगुण्डा क्षेत्रान्तर्गत 17 दिसंबर 2023 को कैंप बेदरे से निकली पुलिस गस्त, सर्चिंग पार्टी पर फायरिंग करने की वारदात में अन्य नक्सली सदस्यों के साथ शामिल थे। उक्त घटना में सुरक्षा बल का 1 जवान शहीद व 1 जवान घायल हुआ। घटना के संबंध में थाना जगरगुण्डा में अपराध क्रमांक 07/2023 धारा 147, 148, 149, 307, 302 भादवि, 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत पूर्व से प्रकरण पंजीबद्ध है।

कुलपति को जान से मारने की धमकी भरा पत्र, निकला भृत्य

बिलासपुर। पंडित सुंदर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति को साधारण डाक से धमकी भरा पत्र भेजने वाले को कोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी विश्वविद्यालय में भृत्य है।19 दिसम्बर 2023 को पंडित सुंदर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बंश गोपाल सिंह को एक साधारण डाक से धमकी भरा पत्र मिला था। फर्जी नाम व पता लिखकर आरोपी ने धमकी भरे पत्र में पुत्र को जान से मारने की धमकी देते हुए वेतन बढ़ाने, नई भर्ती पर रोक लगाने सहित गालीगलौज लिखा था। कुलपति की शिकायत पर कोनी पुलिस मामले की जांच कर रही थी। जांच के दौरान कोनी पुलिस ने विश्वविद्यालय पहुंच कर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का पिछले एक साल के छुट्टी का आवेदन पत्रों को मंगाकर हस्तलिपि से मिलान कर रही थी। लिखावट मेल खाते एक दर्जन से अधिक लोगों को थाने में लाकर पुलिस ने कडाई से पूछताछ की। जांच के दौरान कोनी पुलिस को पता चला कि 6 माह पूर्व विश्वविद्यालय में कार्यरत भृत्य संतोष कुमार पाण्डेय ने कुलपति को नई भर्ती कैसे लोगे मैं देखता हूं कहकर धमकी भरा पत्र लिखा था।

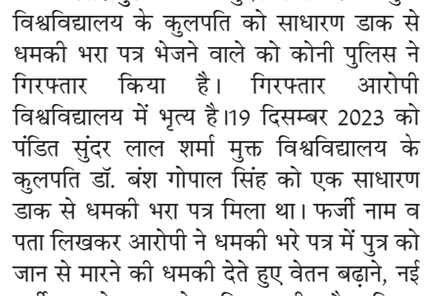

गरियाबंद में नक्सली कैंप ध्वस्त, चलाया ऑपरेशन

गरियाबंद। मटाल पहाड़ी पर डेरा जमाए नक्सलियों के कैंप को सुरक्षा बल के जवानों ने ध्वस्त कर दिया है. बता दें कि कैंप की सूचना पर ई 65, डीआरजी व सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया था. इस दौरान कैंप पर हमला से पहले डेरा छोड़ नक्सली भाग निकले.

गरियाबंद एसपी अमित तुकाराम कांबले को मिली तकनीकी जानकारी के आधार पर आज भालूडीगी के नजदीक मटाल के पास नक्सली कैंप को ध्वस्त करने में जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. डीआरजी कमांडेट वी के सिंह के नेतृत्व में जिला पुलिस बल की ई30, सीआरपीएफ 65 बटालियन साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया. कुल्हाड़ीघाट कैंप से 15 किमी ऊपर पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई कर जवान सीधी मुकाबला के लिए पहुंच गए. तब कैंप में मौजूद 25 से 30 नक्सली मौजूद थे. कैंप में फायर से पहले ब्लास्ट की आवाज सुनकर नक्सली चौकन्ना हो गए. जवानों के साहस के आगे माओवादी बिना मुकाबला किए मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए. एसपी अमित तुका राम कांबले ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कैंप से किराना सामान, छाता, ठंड के कपड़े, पिट्ठू बैग,साहित्य व बर्तन समेत दैनिक उपयोगी सामान जब्त किया गया है.

शिक्षक और पालक भी कार्यक्रम से जुड़ सकेंगे

परीक्षा पर चर्चा में अब पीएम मोदी से 6वीं से 12वीं तक के बच्चे करेंगे संवाद

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर में परीक्षा पर चर्चा से जुड़कर विद्यार्थियों व पालकों से बातचीत करते हैं. पहले कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों से बातचीत करते थे, लेकिन अब कक्षा छठवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों एवं पालकों को परीक्षा पर चर्चा में शामिल किया गया है. वहीं अब रायपुर के संभागीय संयुक्त संचालक डॉक्टर योगेश शिवहरे की पहल पर आगामी परीक्षा के चर्चा पर प्रधानमंत्री से सीधा विद्यार्थी, टीचर और पालक संवाद करेंगे.

डॉक्टर योगेश शिवहरे ने बताया, ब्लैडेट मोड कम समय में अधिक लोगों से संवाद किया जा सकता है. इसके लिए लगातार पंजीयन कराया जा रहा है. रायपुर संभाग के हज़ारों शिक्षकों, पालकों एवं बच्चों को सीधे परीक्षा पर चर्चा में जोड़ने के साथ साथ संभाग में शैक्षणिक वातावरण तैयार करने शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों से सीधे संवाद करने की रणनीति तैयार की गई है. संभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर योगेश शिवहरे की पहल पर आज रायपुर संभाग के पांच जिलों से प्रधानमंत्री के बहु प्रतीक्षित कार्यक्रम

परीक्षा पर चर्चा को लेकर संवाद प्रारंभ किया गया. आज के इस ब्लैडेट मोड में आयोजित वेबिनार में रायपुर महासमुंद गरियाबंद बलौदाबाजार भाटापारा व धमतरी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकुल समन्वयक सहित शिक्षकों ने भाग लिया.

संभाग स्तरीय वेबीनार को संबोधित करते हुए रायपुर संभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर योगेश शिवहरे ने कहा, शिक्षा में आ रही प्रशासनिक दिक्कतों से परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम एक दूसरे से साझा पहल करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बेहतर कार्य करेंगे. स्कूल के संचालन में पालकों को जोड़ने के लिए टीएलएम की व्यवस्था के लिए व पेडागाजी जो सीखना चाहते हैं ऐसे शिक्षकों को पूरा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा.

जो लगातार सीखते रहेंगे वही असली विजेता बनेंगे: राज्यपाल

रायपुर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज 40वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय सब-जुनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुये। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो लगातार सीखते रहेंगे वही असली विजेता बनेंगे।

छत्तीसगढ़ प्रदेश तीरंदाजी संघ द्वारा राज्योत्सव मैदान साइंस कॉलेज रायपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता के अंतर्गत आज राज्यपाल श्री हरिचंदन के मुख्य आतिथ्य में कंपाउंड आरचरी के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया गया।

इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मामले और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्षअर्जुन मुंडा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। श्री हरिचंदन ने प्रतियोगियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी तीरंदाजों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.